RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

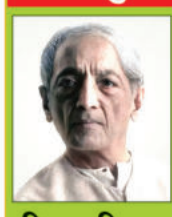

इस बात के प्रति जागरूक हो पाना कि मन किस प्रकार चाल खेलता है, 'समझ' की शुरूआत है।

जे. कृष्णमूर्ती

वर्ष-08, अंक - 17 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरूवार 29 जनवरी 2026 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

हवाई त्रासदी : उपमुख्यमंत्री अजीत पंवर समेत पांच की मौत

बारामती।

महाराष्ट्र के बारामती से बुधवार को एक अत्यंत हृदयविदारक घटना सामने आई, जिसने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया। राज्य के उपमुख्यमंत्री और कद्दावर नेता अजीत पवार का चार्टर्ड विमान बुधवार सुबह बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भीषण हादसे में अजीत पवार सहित विमान में सवार पायलट, सुरक्षाकर्मी और क्रू मेंबर समेत कुल पाँच लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार सुबह करीब 8.10 बजे मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे, जहां उन्हें जिला परिषद चुनावों के सिलसिले में कई जनसभाओं को संबोधित करना था। विमान ने लगभग 8.45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश की, लेकिन लैंडिंग के दौरान अचानक नियंत्रण खो बैठा और रनवे से पहले ही जमीन सेटकराकर आग की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विमान गिरते ही आग का गोला बन गया और आसमान में धुएं के घने गुब्बार दिखाई देने लगे।

हादसे के तुरंत बाद पुलिस, प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। शुरुआती तौर पर यह जानकारी सामने आई थी कि अजीत पवार गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन कुछ ही समय बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

केंद्रीय विमानन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने बताया कि, कॉल' भी नहीं दी गई। दुर्घटना की जांच के लिए विमानन दुर्घटना के समय बारामती एयरपोर्ट पर दृश्यता बेहद खराब थी। उन्होंने बताया कि पहली बार लैंडिंग के दौरान रनवे साफ दिखाई नहीं देने पर विमान को गो-अराउंड किया गया था। दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश में पायलट ने रनवे दिखाई देने की सूचना दी, जब्ब अनुमति भी मिली, लेकिन इसके तुरंत बाद विमान हादसे का शिकार हो गया। मंत्री के अनुसार हादसे के वक्त किसी तरह की 'मेडे महानिदेशालय और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीमें मौके पर पहुंच गई।

इस दुखद घटना से पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बारामती पहुंचे और राज्य सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। अजीत पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 11 बजे बारामती में किया जाएगा। उनके निधन की खबर मिलते ही परिवार के सदस्य, जिनमें उनकी बहन और सांसद सुप्रिया सुले, चाचा शरद पवार, पत्नी सुनेत्रा पवार और दोनों बेटे बारामती पहुंचे। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा थे और अपने सख्त प्रशासनिक निर्णयों व मजबूत राजनीतिक पकड़ के लिए जाने जाते थे। उनके आकस्मिक निधन से न केवल पवार परिवार बल्कि पूरे राज्य की राजनीति को अपूरणीय क्षति पहुंची।

जिले में गौ-हत्या को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन, उधर भारत बीफ एक्सपोर्ट में लगातार बढ़ा रहा अपनी रैंक

माही की गूंज, झाबुआ।
संजय भटेवरा

भारत देश में गाय या गौमाता को लेकर बहुत कुछ कहा-सुना व लिखा जा सकता है। भारतीय संस्कृति में गाय का एक अलग ही स्थान है और कई शास्त्रों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार गाय में कई कोटी के देवताओं का वास भी माना जाता है। लेकिन देश की वर्तमान राजनीतिक स्थितियां इन सबको धत्ता साबित करने में लगी हुई है। अब गाय को भारत में राजनीतिक लाभ और हानि के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसका असर यह होता दिखाई दे रहा है कि, देश में सीधे तौर पर धार्मिक आस्था को राजनीतिक हितों के लिए गहरी ठेंस पहुंचाई जा रही है। जबकि राजनीतिक दल सीधे तौर पर धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते दिखाई दे रहे है। वैसे तो गौ-माता आमजन के लिए आस्था का विषय है लेकिन राजनीति और सरकारों के लिए यह एक बहुत बड़े राजस्व का हिस्सा बन कर रह गई है। देश में गौ-हत्या के कई छोटे-बड़े मामले सामने आते है, जिन्हे राजनीतिक जामा पहना कर धार्मिक रंग दे दिया जाता है। आम लोगों को आपस में लड़वा दिया जाता है और फिर खूब राजनीतिक लाभ उठाया जाता है। मगर इसके उलट देश की सरकार इसी गौ-मांस से बीफ एक्सपोर्ट के नाम पर अरबों रुपयों का राजस्व हासिल कर रही है। राजनीतिक वसीकरण इतना है कि, देश के किसी भी कौने में गौ-हत्या या गौ-मांस को लेकर कोई विशेष कानून नहीं है। यानि सीधे तौर पर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि, गौ-हत्या पर सरकार का कोई प्रतिबंध अब तक देखने को नहीं मिला है। यह और बात है कि, इस देश में गौ-हत्या व आस्था के नाम पर आमजन लड़कर मर रहा है। लेकिन सरकारों को इससे कोई लेना-देना नहीं है। जब कहीं गौ-हत्या का कोई मामला तूल पकड़ता है तो देश के तमाम राजनीतिक दल उसमें अपनी रोटियां सेकते दिखाई देते है।

झाबुआ में गौ-हत्या के विरोध में एवं गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए की मांग को लेकर सकल हिन्दु संगठन का बड़ा प्रदर्शन।

वर्तमान में आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में यह गौ-हत्या का मामला गर्माया हुआ है। झाबुआ जिले के मेघनगर ब्लॉक के ग्राम सजेली, नानियासाथ में पिछले दिसम्बर में एक बहुत बड़ा गौ-हत्या कांड सामने आया। इसको लेकर जिले के तमाम हिन्दु संगठनों ने विरोध किया मगर यह इतना प्रभावशाली नहीं था। सरकारों से केवल आश्वासन के झुनझुने ही कार्रवाई के नाम पर मिले है। हांलाकि पुलिसिया कार्यवाही में कई लोगों की गिरफ्तारियां दर्शाई गई है। अब जिले में इस मामले को लेकर बड़े स्तर पर आंदोलन हो रहे है। मगर क्या यह सब काफी है जिले व देश में गौ-हत्या रोकने के लिए...? जिले में बैठे अधिकारियों ने जिले के हिन्दुओं को आश्वासन का यह झुनझुना भी दिया कि, जिस क्षेत्र में गौ-हत्या हुई है उसे गौ-अभ्यारण बनाया जाएगा। लेकिन इसकी सार्थकता कब और कैसे सार्थक होगी यह किसी को नहीं पता। इसके उलट जब मामला इतना गर्माया तो सरकारों से भी सिर्फ आश्वासन ही मिलते दिखाई दे रहे है।

जब जिले के सजेली नानियासाथ में यह मामला सामने आया था तब माही की गूंज ने इस विषय पर पहल करते हुए विस्तृत खबरें प्रकाशित की थी। तमाम बिंदुओं को अखबार के माध्यम से उठाया था और सरकार से यह सवाल भी किया था कि, गाय अगर हमारी माता है तो फिर इसे राष्ट्रीय पशु क्यों नही घोषित करते...? सवाल अब भी यही है आखिर क्यों सरकारें इस पर इतना ढीला रवैया इख्तियार कर रही है...? जानकारों के मुताबिक यह सरकार के लिए सिर्फ राजनीति करने भर का जरिया है। अगर सरकार गाय को मां मानते हुए इसे राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती है तो करोड़ों रुपए का बीफ एक्सपोर्ट का कारोबार ठप्प हो जाएगा और सरकार को कई अरबों -खरबों का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले तक की रिपोर्ट यह सामने आ रही थी कि, भारत बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया में दूसरे या तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी ताजा मामलों में यह एक पायदान और उपर उठकर पहले स्थान पर पहुंच चुका है। हम इसकी कोई अधिकारिक पुष्टी नहीं करते मगर इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि, जो देश दूसरे या तीसरे स्थान पर बीफ एक्सपोर्ट करने में पहुंच सकता है वह पहले स्थान पर भी पहुंच सकता है।

यह विडम्बना ही कही जाएगी कि, जब धार्मिक मामला आता है तो गाय को राजनीतिक लोग व सरकारें मां बना लेते है, लेकिन जब राजस्व प्राप्ती का मामला आता है तो यही सरकारें और राजनीतिक लोग इसे आमदनी का हिस्सा मानकर इनकी हत्या कर विदेशों में एक्सपोर्ट कर देते है। सरकारों और राजनीति के लिए यह कोई आस्था का विषय नही है। यह महज आमजन के लिए आस्था का विषय हो सकता है। जिससे सरकारों और राजनीति को कोई लेना-देना नही है। पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक दलों पर बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से चंदा लेने के मामले सामने आ चुके है। मगर आस्था केवल आमजन की प्रभावित हुई है। देश के कई प्रदेश ऐसे है जहां खुद सरकारों ने गौकशी और बीफ के कारोबार को खुली छूट दे रखी है। जहां खुलेआम गौ-हत्याएं रोज होती है और गौमांस भी खुलेआम विक्रय किया जाता है।

अब सवाल आम आदमी की आस्था का है तो यह मान लिजिए कि, इसके लिए खुद आमआदमी को ही सड़क पर उतरना पड़ेगा। छोटे-मोटे आंदोलनों से यह किस्सा खत्म होने वाला नही है। इसके लिए पूरे देश में अलख जगानी होगी। गौ-माता में आस्था रखने वाले हर इंसान को खुलकर मैदान में उतरना पड़ेगा। हर राज्य, हर जिले, हर गांव व कस्बे में इस आंदोलन को ले जाने की आवश्यकता है। तभी हम गौ माता को बचा पाएंगे। अन्यथा सरकारें इस देश में कभी गौ-हत्या को बंद करने वाली नही है और ना ही गौ-माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने वाली है।

यूजीसी के समानता नियमों की संवैधानिक वैधता पर बहस

नई दिल्ली, एजेंसी ।

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता बढ़ाने) विनियम, 2026 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने पर सहमति जताई। यह विवाद नए ढांचे को लेकर गहरा रहा है, जो शैक्षणिक परिसरों में जाति-आधारित भेदभाव को दूर करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी राहुल दीवान की ओर से अधिवक्ता पार्थ यादव ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष याचिका का जिक्र किया। यादव ने अदालत से मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया और कहा कि नियमों के लागू होने से भेदभाव हो सकता है, इसलिए इस मुद्दे पर न्यायिक जांच जरूरी है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जवाब देते हुए सुनवाई की तारीख जल्द तय करने पर विचार करने की सहमति जताई और वकीलों से याचिका में मौजूद सभी खामियों को दूर करने को कहा ताकि मामला सूचीबद्ध किया जा सके।

दीवान की याचिका उन कम से कम तीन चुनौतियों में से एक है, जो 2026 के नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। यूजीसी ने यह नियम 13 जनवरी को अधिसूचित किए थे, जो 2012 के पुराने ढांचे को प्रतिस्थापित करते हैं। इनमें से एक याचिका उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पोस्ट-डॉक्टरल शोधकर्ता मृत्युंजय तिवारी ने दायर की है, जबकि दूसरी याचिका मंगलवार सुबह अधिवक्ता विनीत जिंदल ने दायर की।

अदालती कार्यवाही उस व्यापक राष्ट्रीय बहस के बीच हुई, जो यूजीसी द्वारा अधिसूचित नए समानता नियमों पर चल रही है। इन नियमों के तहत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और मान्यता प्राप्त संस्थानों में भेदभाव की शिकायतों के निवारण और समावेशन बढ़ाने के लिए समान अवसर केंद्र और समानता समितियों की स्थापना अनिवार्य है। ये नियम अगस्त 2019 में उच्च शिक्षा में भेदभाव-विरोधी सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग वाली सर्वोच्च न्यायालय की याचिका का परिणाम हैं।

खौफनाक कहर: होटल इलाके के पास गिरा विशालकाय हिमस्खलन

सोनमर्ग।

जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग से हिमस्खलन का एक बेहद डरावना वीडियो सामने आया है, जिसने सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग के होटल जोन के ठीक ऊपर पहाड़ों से अचानक बर्फ का एक विशाल सैलाब नीचे की ओर टूटकर गिरा। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि चंद सेकंड के भीतर बर्फ के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया।

वीडियो फुटेज में साफ दिखाई देता है कि ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से भारी मात्रा में बर्फ तेजी से नीचे खिसक रही है। कुछ ही पलों में यह एक विशाल सफेद बादल की तरह फैल जाती है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि इस भयानक घटना में किसी प्रकार के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों ने राहत की सांस लेते हुए बताया कि बर्फीला सैलाब होटल परिसर से कुछ ही दूरी पर रुक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया।

घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षाबलों और प्रशासनिक टीमों ने प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बर्फबारी ने इस तरह की घटनाओं के खतरे को काफी बढ़ा दिया है। सोनमर्ग और आसपास के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रिकॉर्ड स्तर की बर्फबारी हुई है, जिससे कई स्थानों पर छह फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है।

भारी बर्फ के इस जमाव के कारण पहाड़ी ढलानों पर दबाव बढ़ गया है, जो हिमस्खलन का मुख्य कारण बन रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ताजी बर्फबारी के बाद तापमान में मामूली वृद्धि या तेज हवाएं भी बर्फ की परतों को अस्थिर कर सकती हैं, जिससे अचानक हिमस्खलन की स्थिति पैदा हो जाती है।

आपदा प्रबंधन एजेंसी ने सोनमर्ग सहित कश्मीर के अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए पहले ही मध्यम स्तर का अलर्ट जारी किया हुआ है। प्रशासन ने पर्यटकों, स्थानीय निवासियों और होटल संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि वे सतर्क रहें और ढलान वाले क्षेत्रों या संवेदनशील पहाड़ियों की ओर अनावश्यक आवाजाही से बचें। वर्तमान स्थिति को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में आवाजाही पर अस्थायी रोक भी लगाई जा सकती है। प्रशासन की टीमें किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर हैं और लगातार बदलते मौसम और पहाड़ों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

ऐसी ही त्वरित न्याय व्यवस्था होनी चाहिए

ओरोपी को 44 दिन में मिली मौत की सजा।

माही की गूंज, झाबुआ।
मुजम्मिल मंसुरी

कहते हैं कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के समान ही होता है। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद देश भर में जो आक्रोश देखा गया उसके बाद देश की न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन और कड़े कानून की मांग की गई थी। जिसके बाद हमारे देश के नीति नियताओं ने बाल अपराध और बलात्कार जैसे अपराध के लिए त्वरित न्याय और कठोर सजा का प्रावधान किया है। जिसके बाद इस प्रकार के अपराधियों में भय तो है लेकिन अभी भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। हाल ही में गुजरात के राजकोट में एक मामला सामने आया था और न केवल पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की बल्कि न्यायालय ने भी रिकार्ड स म य 44 दिन म अपराधी को फांसी की सजा देकर देश की न्यायिक व्यवस्था का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। जिसके बाद यही कहा जा सकता है अन्य अपराधों में इसी प्रकार की न्यायिक व्यवस्था होना चाहिए जिसके बाद अपराधियों के मन में देश की न्यायिक व्यवस्था से डर पैदा होगा और आपराधिक गतिविधियों में कमी आएगी।

क्या है मामला गुजरात का

दिल्ली के निर्भया कांड जैसी रूह कपा देने वाली घटना गुजरात में घटी जिसमें महज 7 साल की बच्ची के साथ बेहद जघन्य और दरिंदगी से जुड़ा है, जिसने एक बार फिर देश को झगजोर दिया था। घटना 4 दिसंबर 2025 को राजकोट जिले की आटकोल तहसील का है जहां बगीचे में खेल रही बच्ची को गांव का ही आरोपित व्यक्ति झाड़ियां में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म और अमानवीय कृत्य किया। तथा दर्द से तड़पती लहू लोहान बच्ची को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही राजकोट कि ग्रामीण पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की ओर महज चार दिन बाद यानी 8 दिसंबर 2025 को आरोपी रामसिंह पिता तेरसिंह डुंडवा को गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारियों ने महज 11 दिनों में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद विशेष पाक्सो अदालत ने मामले की सुनवाई को प्राथमिकता देते हुए रोजाना सुनवाई की और 12 जनवरी 2026 को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और 17 जनवरी 2026 को राजकोट की विशेष पाक्सो अदालत ने न्यायाधीश वी.ए. राणा ने आरोपी को फांसी की सजा सुना दी। इस पूरे मामले में देश के न्यायिक व्यवस्था पुलिस और जांच से जुड़े अधिकारियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्योंकि इन्होंने देश की न्याय व्यवस्था को न केवल मजबूती प्रदान की है वरन आम लोगों का विश्वास जीतने का कार्य भी किया है। पुलिसिया जांच में 200 संदिग्धो से पूछताछ की गई और खिलौने के जरिए पहचान परेड करवाई गई। यही नहीं पीडित बच्ची डरी हुई थी इसलिए एक महिला ऑफिसर और एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर से उसकी काउंसलिंग करवाई गई और आरोपी का हुलिया बनवाया गया। तथा हुलिया के आधार पर आसपास करीब 200 प्रवासी मजदूरों से पूछताछ की गई और आखिरकार मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले के जोबट थाना क्षेत्र का रहने वाला 32 वर्षीय शख्स रामसिंह को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस जांच का एक संवेदन पहलू यह भी था कि, हर संदिग्ध को एक खिलौना दिया गया था ताकि बच्चे, आरोपी को देखकर डरे नहीं। जिसके बाद पीड़ित लड़की और उसके साथ खेल रहे बच्चों ने बिना डरे आरोपी की पहचान कर ली। इस केस में सिर्फ 12 दिन के कम समय में सारे मेडिकल, फॉरेंसिक और डॉक्यूमेंट्री सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में चार्ज शीट पेश कर दी। घटनास्थल पर आरोपी के बाल मिले जिसकी फोरेंसिक रिपोर्ट अहम सबूत साबित हुई। चार्ज शीट होने के 29 दिन और एफआईआर होने के महज़ 40 दिन के अंदर कैस को निपटा देना निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है। अन्य संवेदनशील केसों में भी पुलिस जांच और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को भी इसी प्रकार की तेजी दिखाना चाहिए जिससे भारतीय न्याय व्यवस्था और अधिक मजबूत हो।

अवैध रेत का कारोबार चरम पर, बे रोक-टोक अवरलोड सड़कों पर दौड़ रहे रेत के डंपर

कलेक्टर की कार्रवाई हुई ठंडी, खनिज विभाग भी दुबक कर बैठा

माही की गूंज, पेटलावद।
राकेश गेहलोत

कुछ माह पूर्व ही रेत पर चलने वाले डंफर के द्वारा जिला कलेक्टर नेहा मीना के वाहन को टक्कर मार दी गई थी। जिसके बाद जिला कलेक्टर एक्शन में दिखाई दी और जिला खनिज विभाग की ओर से ताबड़तोड़ कार्यवाही रेत के कारोबारियों पर देखने को मिली। जिसमें जिले में कई जगहों पर अवैध रेत से भरे डंफर खनिज विभाग ने पकड़ कर लाखों की पेलेंटी वसूल की। जिस प्रकार से जिले भर में अवैध रेत के कारोबार पर ताबड़तोड़ कार्यवाही की गई लग रहा था कि, अवैध रेत के इस काले धंधे पर रोक लगेगी। जिले से शुरू हुई कार्रवाई कुछ ही दिनों की मेहमान रही ओर अवैध रेत का कारोबार फिर से अपने पूरे चरम पर है। आलम ये है कि, रेत ओवर लोड भरे डंफर बेधड़क नगर की सड़को पर दौड़ने लग गए जिनको रोकने वाला कोई नहीं है।

नगर में रोज आ रहे 20 से 25 डंफर

अवैध रूप से नगर में चारों ओर रेत का कारोबार किया जा रहा है। यहां एक दो नहीं रोज के लगभग 20 से 25 डंफर रेत आती हैं। जिसमें से लगभग डंफर ओवर लोड होते है क्योंकि अंडर लोड डंफर लाना मतलब डंफर मालिक को किसी प्रकार का मुनाफा नहीं मिल पाता। कई वाहनों के पास रॉयल्टी की रसीद तक नहीं होती, तो कई वाहन एक ही रसीद पर आ जाते है। स्थानीय स्तर पर मौजूद दलाल नगर में आए इन डंफर को कमीशन पर ठिकाने लगाते हैं।

शिकायत के बाद भी नहीं होती कार्रवाई, खनिज विभाग गायब

गुजरात ओर आलीराजपुर जिले से रेत भर के ये वाहन दो ,तीन ओर चार जिले पार कर निकल जाते है जिनको रोकने वाला कोई नहीं है। कहने को तो खनिज विभाग का अमला मौजूद है लेकिन रेत के डंफर देख कर ही विभाग दुबक जाता है। आलम ये है कि, कई मीडिया में आई खबरों ओर शिकायतों के बाद भी खनिज विभाग की कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। स्थानीय स्तर के अधिकारी भी रेत के इस अवैध कारोबार को देखा अनदेखा कर दिया जाता है। मंगलवार को चार डंफर अवैध रेत के भरे होने की सूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास गई जहा से मामले को दिखवाने की बात कही गई लेकिन किसी प्रकार की हलचल नहीं देखी गई। उधर रेत की दलाली में लगे दलाल खुल कर एक से डेढ़ लाख की बंदी होने ओर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने की बात खुल कर कहते देखे जा सकते है। वो खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि, ऐसे ही रोज इतनी रेत एक राज्य ओर तीन-चार जिले पार कर यहां ऐसे नहीं पहुंचते। अब इस सेटिंग की बंदरबाट में कौन-कौन शामिल हैं इसकी जानकारी रेत सप्लाई में लगे दलालों के मोबाइल की काल डिटेल से पता लग जाएगी। इस काले कारोबार के पीछे कौन-कौन से विभाग के जिम्मेदार शामिल है।

कलेक्टर से उम्मीद

जिस तरह से अवैध रेत के मामले में कार्यवाही कलेक्टर नेहा मीना ने शुरू की थी उसी प्रकार की कार्रवाई को फिर शुरू करना होगी जिसकी उम्मीद जिला कलेक्टर से है। ताकि रोज की हो रही राजस्व की चोरी को रोका जा सके और अवैध रेत के कारोबार पर रोक लगाई जा सके।

इस मामले में खनिज इंस्पेक्टर संतोष सूर्यवशी से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि, मैं दो-तीन दिन से छुट्टी पर हु आप जिला खनिज अधिकारी भिड़े साहब से बात कर लीजिए बोल कर फोन काट दिया। दोबारा काल करने पर काल तक रिसीव नहीं किया गया। जिससे पता चलता है कि, रेत के अवैध कारोबार में खनिज विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है।

यज्ञ पूर्णाहुति के साथ मना हिंदू सम्मेलन

कलश यात्रा के साथ हुई यज्ञ की पूर्णाहुति।

माही की गूंज, भामल।

ग्राम भामल में सप्त दिवसीय यज्ञ का शुभारंभ 21 जनवरी को शुरू किया गया था। जिसमें पांच जोड़ यजमान बनकर हवन में पूर्ण आहुति दी गई। अंतिम दिन पश्चात हिंदू सम्मेलन के साथ यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई जिसमें ग्राम के धर्म प्रेमियों ने हिंदू सम्मेलन में बढ़-चढ़कर भाग लिया। तथा सुबह कलश यात्रा के साथ हवन की पूर्ण आहुति हुई। जिसके बाद हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिसमें संघ के प्रमुख पदाधिकारी ने मच पर उपस्थित होते हुए उद्बोधन हिंदू सम्मेलन पर दिए बताते हैं।

रजत जयंती महोत्सव सम्पन्न

बच्चों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति देते हुए।

माही की गूंज, भामल।

23 जनवरी को रजत जयंती महोत्सव, पंचकुंडीय महायज्ञ एवं वार्षिक महोत्सव का आयोजन एमडीएच स्कुल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातःकाल पंचकुंडीय महायज्ञ से हुआ।

इस अवसर पर आचार्य विश्वामित्र ने रामायण एवं महाभारत के प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से अभिभावकों को संदेश दिया कि, यदि वे अपने बच्चों को राम और कृष्ण के आदर्शों पर देखना चाहते हैं, तो स्वयं को दशरथ और वासुदेव जैसे आदर्श माता-पिता बनना होगा।

आशा सुपरवाइजर सम्मानित

माही की गूंज, करवड़।

ग्राम की आशा सुपरवाइजर श्रीमति अंगुरबाला शर्मा द्वारा जिले में सर्वाधिक पुरुष नसबन्दी के लिए प्रेरित कर ऑपरेशन करवाने पर 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर कलेक्टर झाबुआ द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष करवड सेक्टर से पुरुष नसबंदी ऑपरेशन करवाए जाते रहे है जिसमें ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एम एल चोपड़ा बीईई विवेक मरकाम एवं सेक्टर सुपरवाइजर दीपक बसेर का मार्गदर्शन एवं सहयोग मिलता रहता है, उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया । इसी प्रकार पेटलावद विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम करवड़ के प्राथमिक शिक्षक जसवंत सिंह पवार को मतदान केंद्र क्रमांक 22 के एसएआर 2025 के कार्य के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया स्टाफ के द्वारा बधाई एवं शुभकामनाएं दी जा रही है।

मादक पदार्थ की शंका में पकड़ा युवको को

माही की गूंज, थांदला।

स्थानीय पुलिस ने 24 जनवरी देर शाम दीप मलिका चौराहे पर दो संदिग्ध युवकों को शक के आधार पर पकड़ा था। पकड़े गए आरोपियों पर मादक पदार्थ तस्करी में शामिल होने का आरोप भी है। पुलिस द्वारा इन दोनों युवकों को थाने ले जाने पर हिंदूवादी संगठनों ने भी थाने का घेराव करते हुए नशीले पदार्थ का विरोध कर कार्रवाई की मांग की। हालांकि पुलिस को इन संदिग्ध व्यक्तियों से कोई माल बरामद नहीं हुआ है। युवको पर 151 का मामला दर्ज किया गया।

संभाग स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में प्राची ने प्रथम स्थान पाया

माही की गूंज, पेटलावद।

क्रांतिसूर्य टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय, खरगोन के तत्वावधान में आयोजित संभाग स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय महाविद्यालय, अलीराजपुर द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में छात्रा प्राची गोपाल सिंह पड़ियार ने 10 किलोमीटर की दौड़ मात्र 37 मिनट में पूर्ण कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उक्त शानदार प्रदर्शन के आधार पर प्राची गोपाल सिंह पड़ियार का राष्ट्रीय स्तर की क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन क्रांतिसूर्य टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय, खरगोन की ओर से 27 फरवरी 2026 को बेंगलुरु (कर्नाटक) में किया जाएगा, जिसमें प्राची विश्वविद्यालय टीम का नेतृत्व भी करेंगी।

यह उपलब्धि उन्हें डॉ. धर्मेंद्र एवं डॉ. गगन चौधरी के कुशल मार्गदर्शन में प्राप्त हुई। उनकी इस सफलता पर महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिवार द्वारा हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ दी गईं।

सट्टेबाजी से युवाओं में दुष्प्रभाव- ऑन लाइन सट्टा बाजार पर सरकार सख्त और कड़े कानून लाए

माही की गूंज, झाबुआ।

सट्टे की सड़क पर युवाओं की तेज रफ्तार अंत में उनसे सबकुछ छीन लेती हैं। यहां तक की कभी तो युवा अपने आप को भी दांव पर लगा देता है और सट्टेबाजी में हार के बाद निराशा होने से युवा अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार की समाज में हानि होने पर ऑनलाइन सट्टा बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सामाजिक रुप से जो क्षति होती है उसका ये सटोरिएं अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए सरकार को सट्टेबाजी पर सख्त कानून लाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में बच्चों में ऑनलाइन गेमींग का प्रभाव इस स्तर पर फैला हुआ है कि, ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चें जीद्दी और हठी स्वाभाव के हो गए है साथ ही साथ मानसिक रुप से अत्यंत कमजोर भी हो गए है। इसके साथ ही सभी प्रकार के ऑनलाइन गेम में ऑनलाइन सट्टे से जुड़े विज्ञापन बच्चों और युवाओं का ध्यान आकर्षित करते हैं, और बहुत सी बार युवा उन गेम्स के मकड़ जाल में फंस जाते हैं। अधिकतर माता-पिता की शिकायत आती है कि, उनके बच्चों से गेमींग में हजारों रुपए खर्च हो गए। कहीं-कहीं जब युवाओं से लगाया गया पैसा गेम और ऑनलाइन सट्टे के माध्यम से वापस नहीं आता है तो पारिवारिक और सामाजिक डर के कारण वे अपनी जान गवां देते हैं। घर का चिराग बुझ जाता है मगर समाज में ऑनलाइन सट्टा बाजार चलता रहा है।

युवाओ के साथ भी स्थिती कुछ इसी प्रकार से होती है। ऑनलाइन सट्टे की शुरुआत में युवा पहले पहल तो जीत जाता है फिर जब वह निरंतर सट्टा खेलने लगता है तो फिर हार उसे औंधे मुंह नीचे गिरा देती है। आज के समय में युवा अपने मोबाइल फोन पर ढेरो एप ऐसे रखता है जो ऑनलाइन सट्टा या तीन पत्ती या क्रिकेट का खेल खिलवाकर पैसो का हेर-फेर करने के साथ सट्टा या जुआ खिलवाते हैं।

सट्टेबाजी में लोग पहले भी हार कर अपनी पुंजी, अपनी जमीन, यहां तक की चल-अचल संपत्ती को भी बेच देते थे। आज के दौर में वही सारी चीजे फेशन के दौर से गुजरती हुई दिखाई देती है और सट्टा खेलने वाला धीरे-धीरे सड़क पर आ जाता है। अंततः उसके पास खाने को भी नहीं बचता हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी से युवाओं में फैलते दुष्प्रभाव का अभी तक कोई उचित या प्रभावशील समाधान नहीं आया है। सरकार ने पहले भी बहुत से ऐसे एप को बंद कर दिया था जो युवाओं को सट्टे और जुए के रंगीन भंवर में डालते थे लेकिन सरकार ने जितने सट्टा एप बंद किए उससे ज्यादा तो नए फिर से शुरु हो गए।

ऑनलाइन सट्टेबाजी का शिकार तो सभी वर्ग के युवक, युवतियां हो रहीं है लेकिन शर्म के कारण अपने सम्मान को यथावत रखने की चाह में मध्यम वर्गीय युवा सट्टे में हानि या भारी क्षति होने पर स्वयं को काल का ग्रास बना देता है। कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत से युवा सट्टे की लत में पड़कर उधार पैसा लेते हैं, और स्वयं को ब्याज के चक्रव्युह में फंसा लेते हैं। ऑनलाइन सट्टे बाजी के लिए युवा ऑनलाइन लोन लेते हैं, और फिर हार जाने के बाद सिर पटक कर रोते हैं। जो धनवान युवा होते हैं वो तो अपने पेरेंट्स को कुछ तो भी झुठ बोल कर पैसा मंगवा लेते हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। निर्धन युवा ज्यादा से ज्यादा अपनी स्कॉलकशीप का उपयोग करते हैं, और नहीं तो पढ़ाई छोड़ वो दिहाड़ी मजदूरी करना शुरु करते देते हैं या फिर वे युवा अपराध की दूनिया में कदम रखते हैं। सरकार द्वारा निर्धन युवा के लिए की गई सारी मेहनत सट्टे के बाजार में लूट जाती है और निर्धन युवा ऑनलाइन सट्टा बाजार में आ कर सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ भी नहीं ले पाता और अपनी स्थिती में सुधार भी नहीं ला पाता।

सट्टेबाजी में लंबी सौदेबाजी अगर हो जाती है तो हार के बाद मान, प्रतिष्ठा पर प्रश्न और दाग के कारण वो अपनी मौत को गले से लगा लेते हैं। सट्टेबाजी जुएंबाजी में युवा अपराध की राह को थाम लेते हैं। सट्टे में हुई किसी प्रकार की भी हानि वो गलती है जिसे फिर से सुधारा नहीं जा सकता है।

सट्टेबाजी के इतने सारे दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम होने पर भी सरकारे, कोई ठोस कदम नहीं उठाती, न ही इस पर किसी प्रकार के कोई कड़े कानून लाती है। कठोर कानून नहीं होने की वजह से सट्टा खिलवाने वाले आसानी से सट्टे जुएं का प्रचार कर उसे लोगों के बीच में खिलवाते हैं।

इन सारे सट्टा बाजार और जुआ बाजार को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है और सट्टेबाजी के सौदागर भरपेट रुपया पैसा बांट देते है। तभी तो पुलिस और प्रशासन सट्टे के खायवालो के सामने या ऑनलाइन गेम के मालिक के सामने नतमष्तक होते हैं।

रिकेश बैरागी

हालांकि, केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स और सूचना तकनीकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि, ऑनलाइन, जुए और सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कानूनी उपाय करने होगें। उन्होंने कहा है कि, पिछले वर्ष ऑनलाइन सट्टा और जुएं की 1097 बेबसाइट्स् पर प्रतिबंध लगाया था।

बहरहाल, जुएं और सट्टे की वेबसाइट्स को बंदकर देना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या को समझ कर सरकार समाधान के ऐसे सुझावो को सशक्त करे की समाज में सट्टा या जुआ मानसिकता का सफाया हो जाएं। जिसके लिए सिर्फ सरकार को विचार ही नहीं केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर सट्टे और जुएं के विरोध में कड़े कानून प्रस्तावित करने होगे, और देश में समाज को एकजुट होकर सट्टा मानसिकता को समाप्त करने के सफल प्रयत्न करने होगे।

खुले में फेंका जा रहा बायो मेडिकल वेस्ट, जिम्मेदार बेखबर

माही की गूंज, खवासा/भामल
सुनील सोलंकी

एनजीटी के सख्त निर्देशों के बावजूद झाबुआ जिले के ग्रमीण अंचलो मे अवैध चिकित्सक स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे अवैध तरीके से कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जिले में जैव चिकित्सकीय कचरे (बायो मेडिकल वेस्ट) के निस्तारण का उचित बंदोबस्त नहीं होना या फिर जानकर भी अनजान होना अवैध व निजी चिकित्सक कर रहे है। अवैध तरीके से व बिना डिग्री के मन माने तरीके से इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन वही बोतल व इंजेक्शन खत्म होने के बाद खुले में फेके जा रहे हैं।

माही की गूंज प्रतिनिधि को जानकारी देते हुए जोरावर सोलंकी ने बताया कि, बाजना मार्ग 8 लाइन पुल के नीचे मेरे खेत की तरफ एक नाले में खुले मे अवैध तरीके से उपयोग किए हुए इंजेक्शन व बोतल खाली पड़े हुए हैं। वही से नाला भी बहता है जिससे कभी कोई बड़ा सक्रमण फेल सकता है। भामल के अवैध चिकित्सक यहां आकर रात के अंधेरे में खाली इंजेशन व बॉटल फेंकते हैं। हमने कई बार इनको मना भी किया, साथ ही पकड़ने की कोशिश भी की लेकिन यह किस समय आते हैं पता ही नहीं चलता है। लेकिन इस तरह से अवैध तरीके से खुले में इस खतरनाक कचरे को फेंक रहे हैं, जिससे बीमारियों के फैलने की आशंका है। जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस और जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए यह ग्रामीणों का कहना है। वही नियमों की बात की जाए तो जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस तरह से खुले में कचरा नहीं फेंकने का सख्त आदेश व निर्देश दे रखा है। लेकिन फिर भी प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए झोलाछाप चिकित्सक इस तरह से खुले में सामग्री फेंक रहे हैं। जिससे कभी भी कोई गंभीर संक्रमण या बीमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है।

अमंग ,जोश ,जुनून और देशभक्ति के साथ मनाया गणतंत्र दिवस

माही की गूंज ,सारंगी।

गणतंत्र दिवस को लेकर नगर में उत्साह देखा गया बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों ने भी इस आयोजन में भाग लिया । मुख्य आयोजन ग्राम पंचायत भवन पर आयोजित किया गया नगर के सभी सरकारी स्कूल एवं प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने पूरे नगर में प्रभात फेरी निकालकर ग्राम पंचायत भवन पर पहुंचे। यहां पर नगर की प्रथम नागरिक सरपंच फूनदी बाई मेडा ने ध्वज फहराया सभी बच्चों ने एवं गांव के वरिष्ठ नागरिकों ने राष्ट्रगान गाकर तिरंगे झंडे को सलामी दी इस अवसर पर सरपंच मेडा ने नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी । उप तहसील कार्यालय पर नायब तहसीलदार अंकिता भिड़े, हाई स्कूल पर प्राचार्य नितिन परमार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर सुरेश कटारा, पुलिस चौकी पर चौकी प्रभारी दीपक देवरे, एम पी ई बी कार्यालय पर जे ई मोहनिया साथ ही नगर के शासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों पर ध्वज फहराया गया । राजनीतिक दलों में भाजपा सारंगी मंडल कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष पप्पू लाल गामड़ एवं ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व जनपद अध्यक्ष हीरालाल डाबी ने ध्वज फहराया।

सभी संस्थाओं पर ग्राम पंचायत सारंगी की ओर से ग्राम पंचायत सचिव हरिराम भूरिया द्वारा प्रसादी की व्यवस्था की गई।

बामनिया में 77 वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया

माही की गूंज , बामनिया।

26 जनवरी के अवसर पर इस वर्ष तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनिश्री कोमल जी के सानिध्य में सरपंच श्रीमती रामकन्या मखोड़ ने झण्डा वन्दन किया एवं मुनिश्री कोमल कुमार जी ठाणा 2 ने गणतंत्र का महत्व बताया इस अवसर पर बामनिया तेरापंथ धर्म संघ के अध्यक्ष पंकज मेहता व राजेश बम एवम तेरापंथ धर्म सभा की मातृ शक्तियां विशेष रूप से उपस्थित रही। इससे पहले मुस्लिम समाज जनों ने 8 बजकर 15 मिनट पर मदरसे में झंडा वन्दन किया, यहां सरपंच श्रीमती रामकन्या मखोड़ ने झंडा वन्दन किया मदरसे पर उपसरपंच बृजभूषणसिंह परिहार मुस्लिम समाज के प्रमुख नोशाद कुरैशी एवं मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित रहे। मदरसे में झंडा वन्दन करने के बाद 8 बजकर 30 मिनट पर ग्राम पंचायत भवन पर झंडा वन्दन सरपंच द्वारा किया गया। जहां नगर के गणमान्य नागरिक ओर पंचगण उपस्थित रहे। आयोजन के अवसर पर ग्राम पंचायत बामनिया के उपसरपंच बृजभूषणसिंह परिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय जैन, सत्यनारायण शर्मा, घनश्याम माहेश्वरी ,संजय लुणावत, रामेश्वर गर्ग, प्रताप सिसोदिया , बलवीर डामर ,बालू भाई गरवाल, कमल लुणावत ,अजय सिसौदिया, बद्री डामर , घनश्याम गुर्जर ,प्रीतम मुणिया ,रमेश डामर ,पप्पू डामर, हेमचंद्र डामर ,सचिन बसोड, झमक पाटीदार ,मानसिंह डामर, कपिल डामर ,सन्दीप कहार, अंकित बसोड़ आदि उपस्थित रहे। बालक व कन्या हायरसेकंडरी शाला के प्राचार्यद्वय एवम स्टाफ पीरूलाल चौहान ,कैलाश वसुनिया ,अशोक शर्मा, ओमप्रकाश ,त्रिपाठी समरथ गोडाल एवम समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। ग्राम पंचायत बामनिया के सचिव मांगीलाल बिलवाल ने समस्त जनता का आभार व्यक्त किया।

भारत ग्लोबल राजनीति में टॉप पर पहुंचा

नई दिल्ली, एजेंसी।

यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के सम्मान में मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में डिनर आयोजित किया गया। इस दौरान उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि भारत ग्लोबल राजनीति में शीर्ष पर पहुंच गया है और यह एक ऐसा विकास है जिसका यूरोप स्वागत करता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में भारत-यूरोप की सोच और नजरिया एक जैसा है। उनका मानना है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना सिर्फ सामूहिक प्रयासों से ही किया जा सकता है। इस डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल समेत कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुईं।

उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि, अगर यूरोप और भारत अपने संसाधनों और ताकत को मिलाएं, तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। इसी सोच के साथ आज दोनों साथ आए हैं। यह भारत-यूरोप मुक्त व्यापार समझौता और साझेदारी का एक अहम मोड़ है। यह केवल साझेदारी की शुरुआत है, आगे और बड़ा सहयोग होगा। भारत और यूरोप दुनिया को एक मजबूत संदेश दे रहे हैं। ऐसे समय में जब दुनिया में मतभेद और तनाव बढ़ रहे हैं, भारत और यूरोप बातचीत, सहयोग और तालमेल का रास्ता चुन रहे हैं। इससे अस्थिर समय में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा। लोग खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे और कारोबार तथा निवेश में निश्चितता आएगी। इन समझौतों के साथ भारत और यूरोप और ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।

राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर में यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में हमारी रणनीतिक साझेदारी बड़ा आर्थिक और भू-राजनीतिक महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि आज के शिखर सम्मेलन के नतीजों पर उन्हें गर्व है। यह एक ठोस विकास है, जिसमें मुक्त व्यापार समझौता, रक्षा साझेदारी और 2030 के लिए संयुक्त रणनीतिक एजेंडा के माध्यम से वैश्विक मुद्दों पर सहकारी नेतृत्व का उदाहरण पेश किया गया है।

62 वर्ष के बुजुर्ग की मौत के बाद भड़का आक्रोश

माही की गूंज, इंदौर।

जिले के भागीरथपुरा में पीने के पानी में सीवरेज मिलने से फैले डायरिया ने महामारी का रूप ले लिया है। बुधवार को 62 वर्षीय खूबचंद बंधैया की मौत के बाद क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। परिजनों का आरोप है कि समय पर एम्बुलेंस और इलाज न मिलने के कारण उनकी जान गई।

इस मामले को मिलाकर स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि इलाके में एक महीने पहले शुरू हुए दूषित पीने के पानी से फैले डायरिया के कारण अब तक 29 लोगों की जान जा चुकी है।

हालांकि, राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच को सौंपी गई डेथ ऑडिट रिपोर्ट में बताया कि भागीरथपुरा में 16 लोगों की मौत पानी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्या के कारण हो सकती है।

मृतक के परिवार वालों के अनुसार, भागीरथपुरा के रहने वाले खूबचंद बंधैया का उल्टी और डायरिया का इलाज चल रहा था। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को किया गया।

बंधैया के बेटे रोहित ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, ÷मेरे पिता पिछले 15-20 दिनों से दूषित पीने के पानी के कारण उल्टी और डायरिया से पीड़ित थे। हम उन्हें भागीरथपुरा के अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गए, जहां उन्हें दवा दी गई। मंगलवार को हमारे घर पर उनकी मौत हो गई.÷

रोहित ने दावा किया कि उसने हेल्थ सेंटर के अधिकारियों से अपने पिता को अस्पताल में भर्ती करने का अनुरोध किया था, लेकिन उनके घर एंबुलेंस नहीं भेजी गई।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भागीरथपुरा पानी के मुद्दे की न्यायिक जांच के लिए हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है। हाई कोर्ट ने आयोग को न्यायिक जांच शुरू होने की तारीख से चार हफ्तों के भीतर एक अंतरिम रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। भागीरथपुरा में दूषित पीने के पानी के कारण उल्टी और डायरिया का प्रकोप दिसंबर के आखिर में शुरू हुआ था।

अधिकारियों के अनुसार, भागीरथपुरा में 51 ट्यूबवेल में दूषित पानी पाया गया और टेस्ट में ई. कोलाई बैक्टीरिया की मौजूदगी पाई गई। इस बैक्टीरिया के कारण भागीरथपुरा में बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला। उन्होंने बताया कि भागीरथपुरा में नगर निगम की पीने के पानी की पाइपलाइन में लीकेज हो गया था, जिससे एक शौचालय का गंदा पानी पानी की सप्लाई में मिल गया था।

राष्ट्रपति का अभिभाषण वीबी जी राम जी का जिक्र होते ही विपक्ष का हंगामा

नई दिल्ली, एजेंसी।

18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला चरण बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति ने सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया।

अभिभाषण के दौरान जैसे ही राष्ट्रपति ने वीबी जी राम जी कानून का जिक्र किया, विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और कानून वापस लो के नारे लगाए। हालांकि, कुछ देर बाद शोर-शराबा शांत हुआ और अभिभाषण जारी रहा। एनडीए सांसदों ने मेज थपथपाकर राष्ट्रपति के वक्तव्य का समर्थन किया।

बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा, जो दो चरणों में आयोजित होगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी और दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक रहेगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें प्रस्तावित हैं। 28 जनवरी और 1 फरवरी को शून्यकाल नहीं होगा।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार सामाजिक न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और भ्रष्टाचार व घोटालों से सख्ती से निपटने में सफल रही है। उन्होंने बताया कि 2014 में जहां सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ 25 करोड़ लोगों तक सीमित था, वहीं अब करीब 95 करोड़ भारतीय इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।

राष्ट्रपति मुर्मू ने खेलों के क्षेत्र में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने महिला क्रिकेट टीम और महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम की विश्व कप जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि 'खेलो भारत' नीति के जरिए खेल संगठनों में पारदर्शिता लाई जा रही है और भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी भी हासिल की है।रोजगार और कौशल विकास पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने बताया कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए 60 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुद्रा योजना के तहत 38 लाख करोड़ रुपये का ऋण जारी हुआ है और पीएम स्वनिधि योजना से 72 लाख लोगों को लाभ मिला है। देश में करीब 2 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हैं, जिनमें 40 प्रतिशत में महिला निदेशक हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि देश में लाखपति दीदियों की संख्या 2 करोड़ तक पहुंच गई है। स्वस्थ नारीदृसशक्त परिवार अभियान के तहत 7 करोड़ महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। उन्होंने यह भी कहा कि माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में हालात सुधरे हैं और सरेंडर के चलते लाखों लोगों को सुरक्षा मिली है। अंत में राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 10 से 11 वर्षों में भारत की नींव मजबूत हुई है और 2026 के साथ देश इस सदी के दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने इसे विकसित भारत की यात्रा का मजबूत आधार बताया।

बजट सत्रः कांग्रेस सांसद ने एनडीए सरकार की प्राथमिकताओं और इरादों पर उठाए सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी।

संसद के बजट सत्र से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उसकी प्राथमिकताओं और इरादों पर सवाल उठाए। सत्र के पहले दिन मसूद ने कहा कि सरकार को राजकोषीय प्रस्तावों को पेश करने से पहले देश के ज्वलंत मुद्दों का समाधान करना चाहिए।

उत्त प्रदेश में हाल ही में हुए घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए मसूद ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का उल्लेख किया और राज्य सरकार की कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस समय देश का ज्वलंत मुद्दा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। यूपी सरकार को उनसे उनकी उपाधि के बारे में पूछने का क्या अधिकार है?

मसूद ने आरोप लगाया कि पहचान धर्म और मतदान के अधिकार को जोड़ने के प्रयास बहुत चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि मतदान करने के लिए आपको यह साबित करना होगा कि आप वैध मतदाता हैं, लेकिन यह पूछना कि आप हिंदू हैं या नहीं, समझ से परे है। वे देश में क्या करना चाहते हैं? वे क्या बदलाव लाना चाहते हैं?

बता दें कि संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश किया जाएगा, जिसमें 2025-26 के लिए अर्थव्यवस्था का विस्तृत आकलन और अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान प्रस्तुत किए जाएंगे। 2026-27 का केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश होना है। सत्र 65 दिनों में 30 बैठकें लेकर 2 अप्रैल को समाप्त होगा। दोनों सदन 13 फरवरी को अवकाश के लिए स्थगित होंगे और 9 मार्च को फिर सत्र शुरू होगा, जिससे स्थायी समितियों को कई मंत्रालयों के अनुदान अनुरोधों की जांच करने का अवसर मिलेगा।

सत्र से पहले एजेंडे की रूपरेखा तैयार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने कहा कि पार्टी कार्यवाही में सहयोग का आश्वासन देते हुए वोट चोरी, एसआईआर, धान खरीद और मनरेगा केंद्रित मुद्दों को उठाएगी। कांग्रेसी अल्पसंख्यक सांसद आजमुद्दीन मसूद ने भी बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार के समग्र कार्यों पर सवाल उठाए।

संपादकीय

खौफनाक पढ़ाई

पिछले दिनों फरीदाबाद में ठीक से पढ़ाई न कर सकने वाली बच्ची की पिता द्वारा पिटाई करने से हुई मौत की खबर ने हर संवेदनशील इंसान को झकझोरा है। यह विश्वास करना कठिन है, कोई पिता इतना क्रूर हो सकता है कि महज गिनती न सीख पाने के कारण बच्ची की जान ले ले। यदि इस घटना के पीछे कोई परोक्ष कारण नहीं है तो निश्चय ही यह घटना किसी भी सभ्य समाज के लिये कलंक ही कही जाएगी। यह शर्म की बात ही है कि इस ज्ञान की सदी में किसी बच्ची की पिता के हाथों पढ़ाई के नाम पर मौत हो जाए। यह विडंबना ही है कि 21वीं सदी में भी हमारे समाज में मानसिक ग्रंथि की वह गांठ नहीं खुल पाई है, जो मानती है कि डर व मारपीट से बच्चों को सिखाया जा सकता है। ऐसी तमाम घटनाएं आज भी हमारे स्कूलों व घरों तक में सामने आती हैं। यदि स्कूल या कोचिंग में किसी बच्चे-बच्ची के साथ पढ़ाई के नाम पर आक्रामक व्यवहार होता है तो उम्मीद की जाती है कि परिवार उसके साथ मुश्किल समय में खड़ा होगा। लेकिन जब घर में माता-पिता ही हिंसक व्यवहार करने लगें तो मासूम किसके भरोसे रहेगा... कहने को देश में बच्चों के साथ होने वाले किसी भी हिंसक व्यवहार को रोकने के लिये तमाम तरह के प्रावधान सुरक्षा कवच उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जब प्रवर्तन एजेंसियां ही उदासीन रहेंगी तो समस्या का समाधान संभव ही नहीं है। पहले तो स्कूलों में ही ऐसे मामलों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, फिर यदि मामला पुलिस या संबंधित विभाग के संज्ञान में आता भी है तो उसे रफा-दफा करने के प्रयास तेज हो जाते हैं। ऐसे मामलों में शिक्षक अभिभावक संगठन की भूमिका पर भी सवाल उठते रहे हैं। जिसमें अकसर शिक्षण संस्था के सुर में बोलने वाले अभिभावकों को ही रखा जाता है। आज भी यह एक गंभीर समस्या है और इसके गंभीर समाधान की जरूरत महसूस की जा रही है।

यह हमारे समाज की विडंबना ही कही जाएगी कि आज भी यह सोच बलवती है कि बच्चों के साथ सख्त व्यवहार से उनकी पढ़ने-लिखने की क्षमता में वृद्धि होती है। जबकि हकीकत यह है कि किसी भी आक्रामक व्यवहार से बच्चों पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देश व दुनिया में हुए तमाम शोध व अध्ययन बताते हैं कि बच्चों के साथ सख्त व आक्रामक व्यवहार किए जाने से बच्चों की एकाग्रता व याद?दाश्त पर प्रतिकूल असर पड़ता है। उनकी निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। जिसका नकारात्मक असर यह होता है कि बच्चे हीनभावना से ग्रसित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी कक्षा में पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। कालांतर यह भय व कुंठा जीवनभर उनका पीछा करती है। उनका आत्मविश्वास डिग जाता है। तब वे जीवन की स्पर्धा में भी दब्बू बनकर रह जाते हैं। यह भी विडंबना ही है कि आज भी बच्चों पर पढ़ाई का बोझ थोपने से पहले हमारे यहां किसी तरह का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण नहीं होता है कि बच्चे की अभिरुचि किन विषयों में है। सही मायनों में हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। कुदरत उसकी रचना किसी खास मकसद के लिये करती है। लेकिन मां-बाप व शिक्षक पहचान नहीं पाते कि उसका रुझान किस दिशा में है। यदि समय रहते बच्चे की उस प्रतिभा को पहचाना जा सके और उस विषय व दिशा में उसे प्रोत्साहित किया जाए, तो वे अप्रत्याशित रूप से किसी भी क्षेत्र में शिखर की सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे कई तरह के जन्मजात व आनुवंशिक रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं, जो उनकी सामान्य पढ़ाई में बाधक हो सकता है। कई बच्चों में जन्म से ही दृष्टि दोष या कोई अन्य शारीरिक व मानसिक विकार भी हो सकता है, जिसके चलते वे अपनी पढ़ाई को ठीक से पूरा नहीं कर पाते। फलत: उन्हें शिक्षकों व परिजनों के हिंसक व्यवहार का शिकार होना पड़ता है। आज बच्चों को संवेदनशील ढंग से देखने की जरूरत है ताकि उनकी पढ़ाई में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर किया जा सके।

एफटीए से यूरोप-भारत व्यापार को बूस्टर डोज

बिना एफटीए के भी यूं तो यूरोपीय देशों से भारत का व्यापार दशकों से होता आ रहा है। लेकिन, ऐसा माना गया कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) होने से इसे बूस्टर डोज़ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए कहा, 'ईयू-इंडिया एफटीए सभी सौदों की जननी है। यह सौदा यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौतों का पूरक है। भारत में कपड़ा, रत्न, आभूषण, चमड़ा और जूट जैसे विभिन्न क्षेत्रों को इस व्यापार समझौते से फायदा होने वाला है।' पीएम मोदी ने कहा कि यह डील भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को मजबूत करेगी, और सर्विस सेक्टर को नया सहारा देगी।

वर्ष 2007 में शुरू हुई वार्ता प्रक्रिया का समापन देर-सवेर हुआ ही। मनमोहन सिंह से आरम्भ वार्ता को मोदी ने अंजाम दिया। यहां तक पहुंचने में 19 साल लगे। लेकिन रुकिए, अभी बहुत कुछ होना बाक़ी है। सभी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की भाषाओं में एफटीए के कानूनी दस्तावेज़ों को प्रकाशित करना होगा। सभी धाराओं की एक-एक करके जांच होगी, जिसे 'लीगल स्क्रबिंग' कहते हैं, यूरोपीय परिषद द्वारा औपचारिक मंजूरी के बाद, यूरोपीय संसद की सहमति चाहिए, इसके प्रकारांतर भारतीय कैबिनेट द्वारा पुष्टि होगी। इन सबसे गुज़रने के बाद, 2027 तक इसके लागू होने की उम्मीद है।

मंगलवार को यूरोपियन कमीशन की प्रतिक्रिया ग़ौर करने लायक हैकृ 'इस डील से ईयू कंपनियों और किसानों को ज़्यादा निर्यात करने में मदद मिलेगी। इस डील से पहले ही आठ लाख यूरोपीय नौकरियों को सपोर्ट मिलता रहा है। अब एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से, और भी ज़्यादा यूरोपीय नौकरियां मिल सकती हैं।' यूरोपियन कमीशन का सन्देश था, 'उम्मीद है कि यह समझौता भारत को होने वाले ईयू एक्सपोर्ट को दोगुना कर देगा। इसके अलावा, भारतीय सर्विस मार्केट तक बेहतर पहुंच, खासकर फाइनेंशियल सर्विसेज़, मैरीटाइम सर्विसेज़ और दूसरे मुख्य सेक्टर्स में, नए बिज़नेस और रोज़गार के अवसर पैदा करेगी।'

यूरोपीय आयोग ने जानकारी दी, कि इस डील से 90 फीसद से ज़्यादा यूरोपीय संघ के देशों के सामानों के एक्सपोर्ट टैरिफ खत्म, या कम कर दिया जाएगा। इससे यूरोपीय प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी में हर साल अरबों यूरो तक की बचत होगी। यूरोपियन कमीशन ने कहा, 'भारत ने किसी भी व्यापारिक सहकार को इतनी बड़ी ट्रेड ओपनिंग नहीं दी है। इससे एक्सपोर्ट को तेज़ और आसान बनाने के लिए कस्टम प्रक्रियाओं को सहज बनाया जायेगा।'

27 जनवरी को डील के तुरंत बाद यूरोपियन कमीशन ने आधिकारिक जानकारी दी कि भारत ईयू को टैरिफ में ऐसी छूट देगा, जो उसके किसी भी दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर को नहीं मिली है, जिससे ईयू एक्सपोर्ट के लिए भारतीय बाजार में पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। उदाहरण के लिए, कारों पर टैरिफ धीरे-धीरे 110 प्रतिशत से घटकर 10 फीसद हो जाएगा, जिसमें हर साल 250,000 गाड़ियों का कोटा होगा। मशीनरी पर 44 प्रतिशत, केमिकल्स पर 22 परसेंट और फार्मास्यूटिकल्स पर 11 प्रतिशत तक के ऊंचे टैरिफ को ज़ीरो पर ले आया जाएगा। टैरिफ एक टैक्स है, जो कोई देश अपने यहां विदेश से आयात होने वाले समान पर लगाता है। इससे विदेश से आने वाला सामान महंगा हो जाता है, और जिस देश में सामान आता है, उसे टैक्स से आय होता है।

यूरोपियन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर एक चार्ट के ज़रिये सारा गणित समझाया है। कमीशन ने वर्ष 2024 को आकलन का आधार बनाया, जिसमें मशीनरी और इलेक्ट्रिकल उपकरण पर 16.3 बिलियन यूरो बतौर टैरिफ देने पड़े थे। एफटीए के कार्यान्वयन के बाद, यूरोपीय संघ के देशों को टैरिफ की देनदारी ज़ीरो प्रतिशत हो जाएगी। विमान और अंतरिक्ष यान निर्यात पर 11 प्रतिशत के हिसाब से 6.4 अरब यूरो टैरिफ के रूप में 2024 में देना पड़ा था, आगे से यह शून्य हो जाएगा। ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल उपकरण के एक्सपोर्ट पर 27.5 प्रतिशत के हिसाब से 3.4 बिलियन यूरो देना पड़ा था, इनमें से 90 फीसद प्रोडक्ट पर शून्य टैरिफ लगा करेगा। प्लास्टिक पर भी ज़ीरो टैरिफ लगा करेगा, जिससे यूरोपीय संघ के देशों को 2 अरब 20 करोड़ यूरो की बचत होगी। केमिकल्स पर 22 प्रतिशत टैरिफ आगे से शून्य हो जायेगा, उससे 3 अरब 20 करोड़ यूरो की बचत होगी। आयरन एंड स्टील पर भी 22 प्रतिशत से शून्य टैरिफ हो जाने से डेढ़ अरब और फार्मास्युटिकल्स पर टैरिफ शून्य हो जाने के बाद 1 अरब 10 करोड़ का फायदा यूरोपीय संघ के देशों को होना है।

इस डील से यूरोपीय संघ के किसानों की बल्ले-बल्ले होनी है। यूरोपियन कमीशन ने समझाया है, 'यह एग्रीमेंट ईयू से एक्सपोर्ट होने वाले एग्री-फूड प्रोडक्ट्स पर अक्सर लगने वाले बहुत ज़्यादा टैरिफ (औसतन 36 प्रतिशत से ज़्यादा) को हटाएगा या कम करेगा, जिससे यूरोपीय किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बाज़ार खुल जाएगा। जैसे वाईन पर 150 प्रतिशत टैक्स है, उसे घटाकर प्रीमियम रेंज के वास्ते 20 परसेंट और मीडियम रेंज पर 30 फीसद टैरिफ लाने के वास्ते सहमति बन गई है। स्पिरिट्स पर टैरिफ 150 प्रतिशत से घटाकर 40 पर ले आएंगे। ईयू देशों से भारत भेजे जाने वाले बीयर पर 110 प्रतिशत टैरिफ है, उसे कम कर 50 फीसद कर देना है। जैतून का तेल, मार्जरीन और अन्य वनस्पति तेल पर जो 45 प्रतिशत टैरिफ लगता था, वो ज़ीरो हो जायेगा। कीवी और नाशपाती पर 33 से घटाकर 10 फीसद, फलों के जूस और नॉन-अल्कोहलिक बीयर पर 55 प्रतिशत टैक्स लगा करता था, आगे से ज़ीरो हो जायेगा, प्रोसेस्ड फूड (ब्रेड, पेस्ट्री, बिस्कुट, पास्ता, चॉकलेट, पालतू जानवरों का खाना) पर टैरिफ 50 प्रतिशत से ज़ीरो कर देंगे। भेड़ के मांस पर 33 फीसद टैरिफ लगाते थे, उसे भी ज़ीरो कर देंगे। सॉसेज और मांस से बने अन्य प्रोडक्ट्स पर जो 110 फीसद तक टैरिफ लगते थे, जब एफटीए लागू होगा, उसे 50 प्रतिशत पर ले आया जायेगा।'

पुष्परंजन

ईयू और भारत, बौद्धिक संपदा अधिकारों को मजबूत करने वाले 'ज्योग्राफिकल इंडिकेशन्स' पर एक अलग से समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जिससे सदस्य देशों के पारंपरिक खेती वाले उत्पादों को भारत में ज़्यादा बेचने में मदद मिलेगी। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन देयर लॉयेन ने कहा कि इससे दोनों पक्षों के लिए लाखों नौकरियां सृजित होंगी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने हामी भरते हुए कहा कि हम दो अरब लोगों के लिए बाजार बना रहे हैं। अब देखना यह है कि यह बहु-प्रतीक्षित समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों, और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के 45 करोड़ लोगों के लिए कितना बड़ा अवसर लेकर आता है। हमें इसका भी इंतज़ार रहेगा कि इस एफटीए का ईयू-अमेरिका और भारत-चीन के उभयपक्षीय संबंधों पर क्या असर पड़ता है।

जजों द्वारा सरकार के खिलाफ फैसले, सजा और ट्रांसफर तय?

भारत में न्याय पालिका को संविधान ने सर्वोच्च स्थान पर रखा है। विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा तथा अंतिम फैसला करने का अधिकार संविधान ने न्यायपालिका को दिया है। अब ऐसा ऐसा लगने लगा है, न्यायपालिका सरकार के अधीन है। सरकार के दबाव में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला करने के लिए बाध्य हैं। यदि जज सरकार की अनुकूलता के अनुसार फैसला नहीं देते हैं, तो पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जजों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनकी वरिष्ठता क्रम को नजर अंदाज करते हुए, उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं। उसको लेकर अब विरोध खुलकर सामने आने लगा है। न्यायपालिका की कॉलेजियम व्यवस्था, हाईकोर्ट ?र सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवालिया निशान लगना शुरू हो गए हैं। यह स्थिति भारतीय संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका के अस्तित्व पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने लगी है। कॉलेजियम की अनुशंसा पर सरकार का विधि मंत्रालय ट्रांसफर आदेश जारी करता है। कॉलेजियम की अनुशंसा में यह उल्लेख होने लगा है, यह अनुशंसा सरकार के अनुरोध पर की गई है। जो अपने आप कॉलेजियम की अधिकारिता को दर्शा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज उज्ज्वल भुइयाँ ने सार्वजनिक रूप से न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका के प्रभाव को स्वीकार किया है। जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर और पोस्टिंग में जिस तरह का हस्तक्षेप सरकार द्वारा किया जा रहा है, उदाहरण स्वरुप हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जज की नियुक्ति हुई है। उस नियुक्ति में 56 जजों की वरिष्ठता को नजर अंदाज किया गया। इसके बाद न्यायपालिका में खदर-बदर मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजों को महत्वपूर्ण मामले दिए जा रहे हैं। सीनियर जजों को कम महत्व के मामले दिए जाते हैं। न्यायपालिका में जिस तरीके से न्याय हो रहा है, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। हाल ही में कई जजों के ऐसे ट्रांसफर किए गए हैं, जो उनके फैसलों के कारण हुए हैं। दिल्ली दंगे के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने हेट स्पीच को लेकर एक फैसला दिया था। फैसला देने के तुरंत बाद रातों-रात उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया। हाल ही में न्यायमूर्ति श्रीधरन का ट्रांसफर सरकार के अनुरोध पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विजय शाह द्वारा एक महिला सेवा अधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को संज्ञान मे लिया था। हेट स्पीच को लेकर दमोह के एक मामले में कार्यवाही की थी। नर्सिंग कॉलेजों में जो घोटाला हो रहा था, इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसी तरह पैरामेडिकल कॉलेज जो बिना किसी मान्यता के चल रहे थे, उन पर रोक लगाई थी। सरकार उनके फेसलों से नाराज थी। कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ करने की अनुशंसा की थी। बाद में सरकार के हस्तक्षेप से उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया। जहां पर उनकी वरिष्ठता खत्म हो गई। अब वह चीफ जस्टिस नही बन पाएंगे। ना सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे।

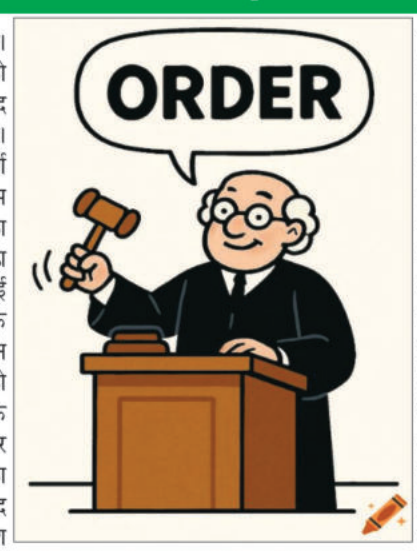

जबकि छत्तीसगढ़ की वरिष्ठता के आधार पर वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते थे।

इस तरह के एक नही बहुत सारे मामले, पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिले हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने सरकार के पक्ष में फैसला नहीं दिया, उन जजों को प्रताड़ित करने का काम कॉलेजियम के माध्यम से सरकार द्वारा किया गया है। जिसके कारण न्यायपालिका की साख आम आदमी की नजरों में कम होती चली जा रही है। इस बात का उल्लेख कोई और नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज भुइयां ने सार्वजनिक कार्यक्रम में किया है। जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर और पोस्टिंग में कार्यपालिका द्वारा जिस तरह का दबाव कॉलेजियम और जजों के ऊपर बनाया जा रहा है। उनका कहना था, न्यायिक तबादले केवल न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए होने चाहिए। अब ट्रांसफर, पोस्टिंग कार्य पालिका के दबाव में सजा के रूप में की जा रही है। इस दखल को उन्होंने गंभीर चिंता का विषय बताया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है, एक बार न्यायपालिका की विश्वसनीयता खत्म हो गई, तो संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना किसी के वश में नहीं होगा। सारे देश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जिस तरह से सरकार के दबाव में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद न्याय पालिका के ऊपर लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। खुलकर न्यायपालिका की आलोचना होने लगी है। अब न्यायालय में जाने के स्थान पर आम लोग राजनेताओं और गुंडे बदमाशों का सहारा लेने लगे हैं। आम आदमी सार्वजनिक स्थलों पर अपना विरोध दर्ज कराने लगे हैं। अभी यह प्रारंभिक स्तर पर है। न्यायपालिका की विश्वसनीयता, निष्पक्षता तथा संविधान के अनुसार फैसला नहीं होने पर जनता का विश्वास न्यायपालिका पर नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में भीड़ तंत्र स्वयं आकर न्याय करने लगता है। इसको राजनीतिक दलों, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को समझना होगा। हाल ही के वर्षों में श्रीलंका, बांग्ला देश, नेपाल और दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों में, जहां न्यायपालिका कमजोर हुई है, सरकारों की दखलंदाजी बढ़ी है। वहां पर भीड़तंत्र ने न्याय पाने के लिए स्वयं अपना रास्ता चुन लिया, जो अत्यंत खतरनाक है। न्यायपालिका की जिम्मेदारी है-जजों की नियुक्ति, उनके ट्रांसफर-पोस्टिंग में पारिदर्शिता हो। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मे जो फैसले हो रहे हैं, समय-समय पर उनका मूल्यांकन होना भी जरूरी है। न्यायपालिका पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सरकार और प्रशासन के साथ मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। न्यायपालिका पर बड़े-बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में फैसला होने की बात सामने आ रही है। हाल ही में राजस्थान के एक जज का ट्रांसफर रातों-रात इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने फैसले में देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति की कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। हाईकोर्ट से उस आदेश को तुरंत स्थगित कर दिया गया। जज साहब का भी ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह के संबंध होने की बात सामने आने लगी है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए बेहद सजगता की जरूरत है। समय रहते उपचार नहीं किया गया, तो भविष्य में क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सत्ता पर अंकुश जरूरी है। यदि अंकुश महावत का नहीं होता है तो मदमस्त हाथी अपनी ताकत के बल पर विनाश ही करता है।

सनत जैन

चुनौतीपूर्ण दौर में रणनीतिक समझौतों की अनिवार्यता

यूएई के राष्ट्रपति का दिल्ली दौरा और हमारे प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत, बगल के पड़ोसी के साथ हमारे ठंडे पड़े रिश्तों के बीच ताज़ी हवा के झोंके जैसा है। अब हमारी निगाह यूरोपियन यूनियन के साथ 'सब समझौतों की जननी' (मदर ऑफ ऑल डील्स) पर लगी है जिसके गणतंत्र दिवस तक संपन्न होने की उम्मीद है। यह समझौता यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे संबंधों को नई गति देगा। जिस नई विश्व व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनज़र द्विपक्षीय संबंधों और मुक्त व्यापार समझौतों का विस्तार करना और भी ज़रूरी हो गया है।

अमेरिका उत्तरोत्तर संरक्षणवादी बनता जा रहा है और पिछली व्यवस्था के बहुत से प्रावधानों को चुनौती दे रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने चीन के अपने हालिया दौरे में चीन के साथ व्यापार समझौते का मसौदा तैयार करते वक्त यही बात कही थी। यह देखते हुए कि हमारे दुश्मन देश हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे, रक्षा/सुरक्षा समझौतों और व्यापार गठबंधनों की ज़रूरत और भी अपरिहार्य बन गई है।

ज़रूरी है कि सत्ता में बैठे लोग इस पर आत्म-मंथन करें। क्या महज इस तथ्य के आधार पर कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत विशाल है और हमारा व्यापार भी बहुत ज़्यादा है, उससे हम अपने पड़ोसी पर अजेयता का अहसास करने लगें? तो यह भी पूछा जाए कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को व्हाइट हाउस, पेंटागन, बीजिंग, रियाद, अंकारा आदि में इतना सम्मान क्यों मिल रहा है? पाकिस्तान को चीन से आर्थिक और सैन्य सहायता मिली है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी हथियारों ने प्रदर्शन किया, भले ही चीन के साथ हमारा व्यापार 150 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जबकि इसकी तुलना में पाकिस्तान और चीन का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 15-20 बिलियन डॉलर है। लेकिन उनके पास सीपीईसी (चीन-पाक आर्थिक गलियारा) है जो ग्वादर बंदरगाह के साथ, मध्य पूर्व और यूरोप के लिए चीनी बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) का प्रवेश द्वार है। पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी (पाक अधिकृत कश्मीर में) चीन को सौंप दी थी (जिस पर हमें ऐतराज है) और जहां से होकर काराकोरम राजमार्ग गुज़रता है (जो बीआरआई का अहम हिस्सा है) और यह दोनों देशों के प्रगाढ़ रणनीतिक भाईचारे को दर्शाता है। दूसरी ओर, चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, और चीनी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। इसके मद्देनजर अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी शस्त्रागार में पूर्ववत आर्थिक व सैन्य मदद आती रहेगी।

इसके अलावा, उन्होंने अब सऊदी अरब के साथ एक सुरक्षा समझौता किया है जो ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मदद का आश्वासन देता है। एक नए प्रस्तावित त्रिपक्षीय गठबंधन में तुर्की की पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मिलकर मिनी-नाटो जैसा गठबंधन बनाने की उम्मीद है। याद रखें कि पाकिस्तान के साथ हालिया टकराव के दौरान तुर्की ने ही एकजुटता दिखाने के लिए अपना एक युद्धपोत भेजा था, और कथित तौर पर लड़ाई में उसके बनाए ड्रोनों का भी इस्तेमाल किया गया था। यहां भी, भारत-सऊदी द्विपक्षीय व्यापार 40 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जबकि पाक-सऊदी व्यापार सिर्फ़ 5 बिलियन डॉलर...फिर भी उनके बीच रक्षा समझौता है। पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब को उसकी सुरक्षा ज़रूरतों के लिए सैनिक मुहैया करवाता रहा है और इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि वह एकमात्र इस्लामिक देश है जिसके पास परमाणु क्षमताएं हैं। हाल ही में इस्राइल द्वारा कतर में और अमेरिका द्वारा ईरान पर बमबारी को देखते हुए लगता है कि तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा समझौते के पीछे भू-राजनीतिक

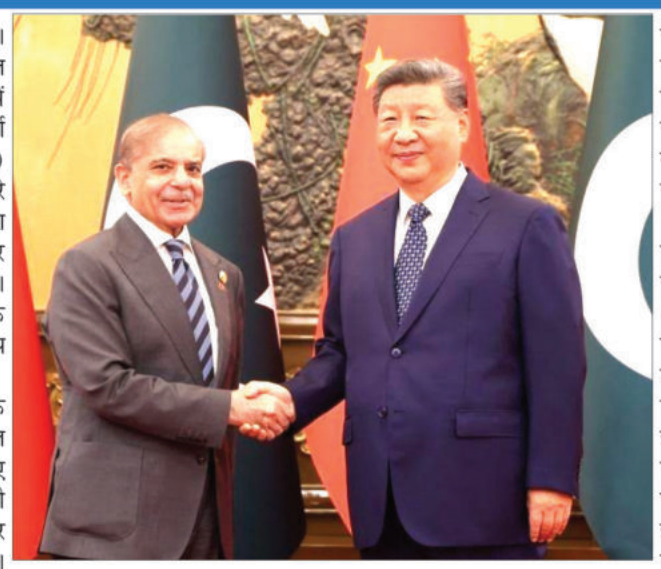

मजबूरियां हैं। अल जज़ीरा के एक हालिया लेख के अनुसार, पाकिस्तान एशिया और अफ्रीका के कई देशों को फाइटर जेट बेचने जा रहा है। जेएफ-17 लड़ाकू जेट चीन और पाकिस्तान के संयुक्त उपक्रम में बनाए जा रहे हैं, और इसके नवीनतम ब्लॉक 3 वेरिएंट को 4.5 जेनरेशन के लड़ाकू विमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 25-30 मिलियन डॉलर की अपेक्षाकृत कम कीमत के साथ इसे कई वायु सेनाओं द्वारा आकर्षक विकल्प माना जा रहा है। यह देखते हुए कि भू-राजनीतिक ताकतें खेल कर रही हैं जो केवल व्यापारिक संबंधों पर हावी हो रही हैं, जब तक हम एक सशक्त सक्रिय नीति नहीं अपनाते, हम खुद को उतरोत्तर अलग-थलग पड़ते पा सकते हैं।

अमेरिका अभी भी बड़ी समस्या बना हुआ है, और उसने हाल ही में फिर से इस्लामाबाद की ओर नर्मी भरा रुख अपनाया है। मामलों को और जटिल बनाने के लिए, अमेरिकी टैरिफ और प्रतिबंधों का खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है। इसके परिणामस्वरूप न केवल हमारे निर्यात में मंदी आई, बल्कि रूस से हमारे तेल आयात में भी भारी कमी करनी पड़ी है।

रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा पड़ा है, और यह हमारे लिए अच्छा नहीं क्योंकि हमारा मुख्य हथियार आपूर्तिकर्ता वही है किंतु फिलहाल उसे अपनी ज़रूरतें पहले पूरी करनी हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों के खतरे के कारण हमें ईरान के साथ हुए उस समझौते से पीछे हटना पड़ रहा है, जिसके जरिए हमें चाबहार बंदरगाह को विकसित और इस्तेमाल करने में मदद मिली थी, और यह ईरान के साथ बचे-खुचे व्यापार को भी रोक देगा, जो पिछले प्रतिबंधों की वजह से पहले ही काफी कम हो चुका। ईरान पारंपरिक रूप से हमारे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। चाबहार बंदरगाह हमें ईरान और मध्य एशिया तक पहुंच मुहैया कराता है। हालिया खबरों के अनुसार, बंदरगाह के भविष्य पर अमेरिका के साथ चर्चा हो रही है।

आखिर में, कश्मीर का पुराना सवाल पहले की भांति कायम है, चीन के समर्थन वाला पाकिस्तान हमेशा यथास्थिति बदलने के मौके की ताक में रहता है। उनके दावों और बातों को हम केवल दिवास्वप्न कहकर खारिज नहीं कर सकते। चीन सीमाओं पर नागरिक एवं सैन्य बुनियादी ढांचे को नए स्तर पर ले जा रहा है, चाहे अग्रिम सीमांत एयरबेस हों या सड़कें वगैरह, जैसाकि हम भी कर रहे हैं, लेकिन पैमाना अलग है।

बांग्लादेश में बदले हुए राजनीतिक हालात ने मामलों को और जटिल बना दिया तथा आज उनके वरिष्ठ नेता खुलेआम पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से काटने की वकालत करते सुने जा रहे हैं। इस तथ्य के मद्देनज़र कि मणिपुर में स्थिति शांत नहीं और नागालैंड में समस्या अनसुलझी है, यह हमारे पूर्वोत्तर को असुरक्षित और उपद्रवों के लिए खुला छोड़ देता है। लद्दाख में भी अशांति है और मणिपुर की तरह वहां भी त्वरित समाधान जरूरी है। अगर रूस उलझा हुआ है और अपने सहयोगियों की मदद करने में असमर्थ है और अमेरिका प्रतिबद्ध नहीं है, तो हम मदद के लिए किसकी ओर देखेंगे? यह समय चतुर कूटनीति का है ताकि हमारे खिलाफ़ और नए गठजोड़ को रोका जा सके। हम चीन, सऊदी, यूएई, अमेरिका वगैरह के साथ भारी मात्रा में व्यापार करते हैं, हमें अपने रणनीतिक लक्ष्यों के लिए इसका फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि सभी बड़ी शक्तियों ने व्यापार को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। मज़बूत विदेश नीति एक मज़बूत एकजुट राष्ट्र की नींव पर आधारित हो।

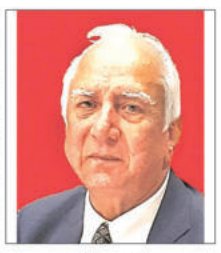

गुरबचन जगत

राष्ट्रीय नेतृत्व की ज़िम्मेदारी है कि वह हमें एकजुट रखे, और यह एकता हमारी अपनी गलतियों और स्वार्थी लक्ष्यों के कारण कमज़ोर न पड़ने पाए। केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे कामकाजी संबंध होने चाहिए। सभी महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्य सरकारों को साथ रखे और उनके नेतृत्व को राष्ट्रीय प्रयासों में शामिल करे। यह रणनीति हमारी सभी आंतरिक सुरक्षा समस्याओं में बहुत कारगर रही है।

भारत की आर्थिक सफलता हमारे पड़ोसियों में ईर्ष्या और दुश्मनी पैदा करती है और इसलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी सुरक्षा और रणनीतिक गठबंधन बनाने पर कहीं ज़्यादा ध्यान दें।

प्रेम विवाह पर पंचायत का तुगलकी फरमान

माही की गूंज, रतलाम।

जिले की पिपलोदा तहसील के पंचेवा गांव में पंचायत ने प्रेम विवाह करने वाले परिवारों पर सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का फैसला सुनाया है। यह आदेश गांव की बैठक में पारित किया गया। पंचायत का कहना है कि बीते छह महीनों में आठ युवक युवतियां प्रेम विवाह के लिए घर से भागे। इसी को रोकने के लिए यह कठोर कदम उठाया गया।

किन परिवारों को बनाया गया निशाना?

जिन परिवारों के बच्चों ने प्रेम विवाह किया है, उनके नाम गांव की बैठक में सार्वजनिक रूप से पढ़े गए। पंचायत के अनुसार ऐसे परिवार गांव की परंपरा के खिलाफ गए हैं। इसलिए उन्हें समाज से अलग रखने का फैसला लिया गया। इस फरमान के बाद गांव में इन परिवारों की पहचान अलग कर दी गई।

कौन कौन सी पाबंदियां लगाई गईं?

इन परिवारों पर कई सख्त रोक लगाई गई है। नाई और पंडितों को उनसे कोई काम न करने का आदेश दिया गया है। कोई भी ग्रामीण उनसे दूध या अन्य सामान नहीं खरीदेगा। उनकी खेती की जमीन कोई पट्टे पर नहीं ले सकेगा। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में उन्हें बुलाने पर भी रोक लगाई गई है।

मदद करने वालों को क्या सजा मिलेगी?

पंचायत के आदेश में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इन परिवारों की मदद करेगा, शादी का गवाह बनेगा या उन्हें आश्रय देगा, उसे भी समाज से बाहर कर दिया जाएगा। यानी एक परिवार नहीं बल्कि पूरे गांव पर डर का माहौल बना दिया गया है। यह फैसला गांव के लोगों पर दबाव बनाने जैसा माना जा रहा है।

ग्रामीण फैसले का बचाव क्यों कर रहे हैं?

गांव के कुछ लोग इस फैसले का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार युवक युवतियों का घर से भागना बच्चों पर गलत असर डाल रहा है। ग्रामीणों का तर्क है कि सख्ती जरूरी थी ताकि आगे कोई ऐसा कदम न उठाए। पंचायत इसे सामाजिक अनुशासन का मामला बता रही है।

पीड़ित परिवारों में गुस्सा क्यों है?

जिन परिवारों पर यह फरमान लागू हुआ है, उनमें भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि यह फैसला गैरकानूनी है। परिवार अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वे जिला प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग करने की तैयारी में हैं। कई परिवार रतलाम कलेक्टर से शिकायत करने की योजना बना रहे हैं।

प्रशासन ने क्या रुख अपनाया है?

वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। जावरा एसडीएम सुनील जायसवाल ने स्पष्ट कहा है कि प्रेम विवाह के कारण किसी परिवार का बहिष्कार अवैध है। प्रशासन गांव वालों से बातचीत कर रहा है। कानून समझाया जा रहा है। वीडियो की जांच की जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई की बात कही गई है।

बंदूक दुकान धमाके में घायल दुकानदार यूसुफ अली की इंदौर में मौत

माही की गूंज, रतलाम।

शहर के चांदनी चौक क्षेत्र स्थित एक बंदूक दुकान में हुए धमाके के मामले में घायल दुकानदार की मौत हो गई। 58 वर्षीय यूसुफ अली ने इलाज के दौरान मंगलवार देर रात दम तोड़ दिया।

प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें रतलाम से इंदौर रेफर किया गया था। मालूम हो कि 26 जनवरी की शाम करीब 4 बजे चांदनी चौक स्थित बंदूक की दुकान में अचानक तेज धमाका हो गया था।

धमाके होते ही दुकान में मौजूद लोग अपनी जान बचाकर बाहर की ओर भागे। हादसे में चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, झुलसे हुए लोग जलती हालत में सड़क पर दौड़ते नजर आए। आसपास की दुकानों में बैठे लोग भी घबराकर बाहर निकल आए। सामने सड़क पर खड़े मैजिक वाहन से सवारियां उतरकर भागती दिखीं।

तीन घायलों का इंदौर में चल रहा इलाज

इस हादसे में दुकानदार यूसुफ अली, 32 वर्षीय नाजिम, 35 वर्षीय शेख रफीकुद्दीन तथा ग्राहक तितरी निवासी 35 वर्षीय संदीप पाटीदार घायल हुए थे। यूसुफ अली की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य तीन घायलों का इलाज इंदौर में जारी है।

हादसे के बाद प्रशासन की टीम ने सुरक्षा की दृष्टि से दुकान को सील कर दिया था। बुधवार को दुकान की सील खोलकर फोरेंसिक टीम द्वारा विस्तृत जांच की जाएगी। पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञ संयुक्त रूप से यह पता लगाएंगे कि दुकान में धमाका किन कारणों से हुआ।

अलग अलग स्थानों से अवैध शराब जप्त

माही की गूंज, मंदसौर।

जिला आबकारी अधिकारी रामहंस पचौरी द्वारा बताया गया कि गणतंत्र दिवस पर्व के अवसर पर घोषित शुष्क दिवस के दौरान मंदसौर जिले में अवैध शराब विक्रय के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कर्मेन्द्र सांवले आबकारी उप निरीक्षक, वृत-मंदसौर द्वारा अजीजखेड़ी रोड़ मंदसौर पर राजु पिता कालुलाल दर्जी के कब्जे से 17 पााव देशी मदिरा प्लेन मदिरा जप्त किये गये, राणा जी होटल मंदसौर पर पंकज पिता गिरधारीलाल सूर्यवंशी के कब्जे से 10 पाव देशी मदिरा प्लेन एवं 07 पाव देशी मदिरा मसाला तथा 03 बीयर केन, महाराजा ढाबा मंदसौर पर चेतन पिता ब्रजलाल रेबारी के कब्जे से 03 बीयर केन एवं 11 पाव देशी मदिरा प्लेन, कृषि उपजमण्डी मंदसौर के पास ओमप्रकाश पिता शम्भूलाल चमार के कब्जे से 23 पाव देशी मदिरा प्लेन एवं 04 बीयर केन तथा 03 पाव देशी मदिरा मसाला, अभिनंदन नगर मंदसौर पर संजय पिता बकंट बप्पा के कब्जे से 15 पाव देशी मदिरा प्लेन एवं 06 पाव देशी मदिरा मसाला, 500 क्वाटर मंदसौर पर धर्मेन्द्र पिता दिलीप सिंह के कब्जे से 12 पाव देशी मदिरा प्लेन, मुन्दडी मे राहुल पिता नाहरसिंह राजपूत के कब्जे से 07 पाव देशी मदिरा प्लेन एवं 03 पाव देशी मदिरा मसाला व 03 बीयर केन जप्त किये जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। वही वृत सुवासरा प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक श्री अमित तेकाम द्वारा अशोक पिता भेरूलाल प्रजापत निवासी ढाबलादेवल के कब्जे से 08 लीटर हाथ भट्टी शराब, यशवंत पिता रामनिवास बारेट निवासी गसोई के कब्जे से 13 पाव देशी मदिरा प्लेन जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किये गये तथा वृत प्रभारी गरोठ /भानपुरा आबकारी उप निरीक्षक संजय राठौर द्वारा द्वारकालाल पिता महादेव मीणा निवासी मोखमपुरा के कब्जे से 11 लीटर हाथ भटटी शराब, देशराज सिंह पिता भवानीसिंह चन्दावत निवासी झिरनिया के कब्जे से 12 पाव देशी मदिरा प्लेन, राहुल पिता सुन्दरलाल प्रजापति निवासी भानियाखेडी के कब्जे से 09 पाव देशी मदिरा प्लेन, नानालाल पिता मांगीलाल बागरी निवासी बर्डियाइस्तमुरार के कब्जे से 11 पाव देशी मदिरा प्लेन जप्त किये जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। आरोपियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 संशोधन 2000 की धारा 34(1) के तहत् कुल 13 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। उक्त कार्यवाही मे आरक्षक सिद्धार्थ, केशव, रवी, अंकित, महेश, कपील, श्रीमती ममता, पंकज, कु. किर्ती का योगदान रहा। अवैध रूप से मदिरा की बिकी, परिवहन, संग्रहण आदि पर रोक लगाने हेतु आबकारी विभाग की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

छापा पड़ा तो भाग निकले मां-बाप

दतिया। पुलिस की वर्दी के अंदर भी एक इंसान होता है। खासकर महिला पुलिस अधिकारी के दिल बहुत संवेदनशील होते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब वर्दी वा मां को भी एक मासूम पर ममता आ गई। दरअसल, फुलरा गांव में अवैध शराब की सूचना पर चिरुला थाना पुलिस और आबकारी विभाग की टीम कंजर डेरा पहुंची तो वहां मौजूद महिला और पुरुष तो भाग गए, लेकिन डेरा पर पुलिस को कुछ बच्चे मिले। इन बच्चों में रोता बिलखता एक मासूम भी मिला। मासूम को देखकर पुलिस की टीम में शामिल महिला पुलिस अधिकारी आकांक्षा जैन के अंदर की ममता जाग उठी। एसडीओपी आकांक्षा जैन ने बच्चे को गोद में लेकर दुलार किया, फिर बच्चे को बोतल से दूध पिलाया और गर्म कपड़े पहनाए। वर्दी में एक अधिकारी को इस तरह बच्चे की देखभाल करते देख वहां मौजूद स्टाफ और ग्रामीण भी भावुक हो उठे। एसडीओपी का बच्चे को प्यार-दुलार लुटाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो 25 जनवरी का बताया जा रहा है। लोग 'वर्दी वाली मां' कहकर आकांक्षा जैन की तारीफ कर रहे हैं।

पिता ने डांटा तो नाराज हुआ बेटा, ऑटो में फांसी लगाकर दे दी जान

माही की गूंज, रतलाम।

शहर के नूरी नगर इलाके में एक दुखद घटना हुई है। बताया जा रहा है कि पिता की डांट से 15 साल के एक लड़के ने आत्महत्या कर ली। यह घटना सालाखेड़ी चौकी इलाके में हुई।

नाबालिग ने अपने घर के बाहर खड़े ऑटो रिक्शा में फांसी लगा ली। इस घटना से इलाके में मातम का माहौल है।

मृतक की पहचान महमूद (15) के रूप में हुई है। उसका शव उसके घर के सामने खाली प्लॉट में खड़े ऑटो रिक्शा के पास संदिग्ध हालत में मिला। आस-पास के लोगों ने जब उसे बेहोश देखा तो तुरंत उसके परिवार को बताया। उसकी मां मौके पर पहुंची और अपने बेटे की हालत देखकर डर गई।

पिता ने अपने बेटे को डांटा था

पड़ोसियों की मदद से लड़के को रात करीब 8 बजे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर उसके पिता भी अस्पताल पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक, मरने वाले के पिता के पास तीन ऑटो रिक्शा थे। शुरुआती जांच में पता चला कि शनिवार शाम करीब 7 बजे पिता एक पैसेंजर को छोड़ने जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने बेटे को कुछ लड़कों के साथ घूमते देखा। उन्होंने ऑटो-रिक्शा रुकवाया, उसे डांटा और बुरी संगत से दूर रहने की सलाह दी। इसके बाद वे वहां से चले गए।

घर लौटने के बाद, बताया जा रहा है कि टीनेजर बाहर खड़े दूसरे ऑटो-रिक्शा में बैठ गया। परिवार के मुताबिक, वह कुछ देर वहां शांति से रहा। बाद में, आरोप है कि उसने ऑटो-रिक्शा में मिली रस्सी का इस्तेमाल करके यह बड़ा कदम उठाया। घटना का पता तब चला जब पड़ोसियों ने उसे संदिग्ध हालत में देखा।

बॉडी पोस्टमॉर्टम के लिए भेजी गई

घटना के बाद, कुछ देर के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तनाव की स्थिति बनी रही। डॉक्टरों ने बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजने का सुझाव दिया, लेकिन परिवार शुरू में राज़ी नहीं हुआ। एएसआई बबलू डागा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिवार को समझाया। काफी बातचीत के बाद, परिवार रात करीब 10 बजे पोस्टमॉर्टम के लिए मान गया। पुलिस ने बताया कि किशोरी के गले पर निशान मिले हैं और ऑटो-रिक्शा के पास एक रस्सी भी मिली है। जांच में यह भी पता चला कि रस्सी ऑटो के अंदर बंधी हुई थी, जबकि शव बाहर की तरफ झुका हुआ था।

प्रेमी की बांहों में थी मां, बेटे ने बना लिया आपत्तिजनक वीडियो

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां अवैध संबंधों ने एक बार फिर एक परिवार की खुशियां उजाड़ दीं। यहां एक बेटे पर उस वक्त खून सवार हो गया जब उसने अपनी मां को गांव के ही एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। मां को प्रेमी की बांहों में देख बेटा आपा खो बैठा और मां के प्रेमी को बेरहमी से पीट दिया। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

मां को प्रेमी की बांहों में देखा

हैरान कर देने वाला मामला मंदसौर जिले के गरोठ थाना क्षेत्र के एक गांव का है। जहां रहने वाले अजय नाम के युवक ने अपनी मां को 19 जनवरी 2026 को गांव के ही रहने वाले राजाराम के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। मां को प्रेमी के साथ देख अजय बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने पहले तो मोबाइल से दोनों का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और फिर लाठी से प्रेमी राजाराम को बेरहमी से पीट दिया। लोगों ने किसी तरह बीच बचाव किया और गंभीर रूप से घायल राजाराम को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां से गंभीर हालत में उसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया।

पुलिस को दिखाया वीडियो

इलाज के दौरान गुरुवार को झालावाड़ में घायल राजाराम की मौत हो गई। इधर जब ये बात अजय को पता चली तो खुद पुलिस थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। आरोपी अजय ने वो वीडियो भी पुलिस को बताया जिसमें उसकी मां व राजाराम आपत्तिजनक हालत में नजर आ रहे थे। गुरुवार को राजाराम गुर्जर की मौत के बाद पुलिस ने हत्या की धारा बढ़ाई है और आरोपी अजय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में 77 वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास एवं गरिमामय वातावरण में समारोहपूर्वक मनाया गया। जिलास्तरीय मुख्य कार्यक्रम स्थानीय राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय के क्रीड़ा परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग ने झंडा वंदन किया तथा परेड की सलामी ली। जिलास्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर श्रीमती गर्ग द्वारा मुख्यमंत्री जी का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन किया गया। संदेश वाचन के पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा रंग-बिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़े गए। इस अवसर पर सांसद श्री बंशीलाल गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार, मंदसौर विधायक विपिन जैन, पूर्व मंत्री कैलाश चावला, जिला योजना समिति सदस्य राजेश दीक्षित, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमा देवी बंशीलाल गुर्जर, नपा उपाध्यक्ष श्रीमती नम्रता प्रीतेश चावला सहित अन्य जनप्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना, अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनुकूल जैन, एएसपी तेरसिंह बघेल, न्यायाधीशगण, जिला अधिकारीगण, पार्षदगण, मीडिया प्रतिनिधिगण एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित रहे। जिलास्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में 15 प्लाटून विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल पुरुष, जिला पुलिस बल महिला, जिला होमगार्ड बल, एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज, एनसीसी सीनियर डिवीजन गर्ल्स, एनएसएस, एनसीसी जूनियर डिवीजन सेंट थॉमस, एनसीसी जूनियर डिवीजन सरदार वल्लभभाई पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2, एनसीसी जूनियर डिवीजन उत्कृष्ट स्कूल, स्काउट उत्कृष्ट स्कूल, गाइड दल सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल मंदसौर, शौर्यदल महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल, रेड क्रॉस शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालागंज एवं फंटलाइन वर्कर, पुलिस बैंड द्वारा आकर्षक परेड आयोजित की गई। सधी हुई परेड में सीनियर डिवीजन में प्रथम पुरस्कार एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज, द्वितीय पुरस्कार जिला पुलिस बल महिला एवं तृतीय पुरस्कार जिला होमगार्ड बल को प्रदान किया गया। जूनियर डिवीजन में प्रथम पुरस्कार एनसीसी जूनियर डिवीजन सरदार वल्लभभाई पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2, द्वितीय पुरस्कार एनसीसी सेंट थॉमस तथा तृतीय पुरस्कार स्काउट एवं गाइड सांदीपनि हायर सेकेंडरी स्कूल मंदसौर को दिया गया।

विभिन्न विद्यालयों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में प्रथम पुरस्कार सेंट थॉमस स्कूल एवं द्वितीय पुरस्कार वात्सल्य पब्लिक स्कूल मंदसौर को प्रदान किया गया। महावीर व्यायाम शाला द्वारा मलखंब की आकर्षक प्रस्तुति तथा आईपीएस इंग्लिश स्कूल द्वारा मार्शल आर्ट का शानदार प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिविल डिफेंस एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। डिप्टी चीफ वार्डन डॉ. हिमांशु यजुर्वेदी एवं उनकी टीम द्वारा सांप के काटने से बचाव एवं आकाशीय बिजली से सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं पर आधारित आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गईं। झांकियों में प्रथम पुरस्कार आपदा प्रबंधन विषय पर आधारित होमगार्ड विभाग को, द्वितीय पुरस्कार महिला एवं बाल विकास विभाग को तथा तृतीय पुरस्कार स्काउट शिक्षा विभाग को प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि कलेक्टर श्रीमती अदिती गर्ग द्वारा लोकतंत्र सेनानी का शाल एवं श्रीफल से सम्मान किया गया। कार्यक्रम के समापन पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, साहसिक कार्य करने वाले नागरिकों एवं विभागों को शील्ड, प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. जे. के. जैन द्वारा किया गया।

19 दिन चली सर्चिंग, झाबुआ के 3 कुख्यात बदमाश धराए

माही की गूंज, खंडवा।

जिले के पुनासा में सराफा व्यापारी के साथ हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। झाबुआ के कुख्यात गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से करीब 71.5 लाख रुपए की ज्वैलरी, 1 लाख रुपए नकद, एक 12 बोर की देसी पिस्टल और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि घटना में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि 9 जनवरी की शाम करीब 7 बजे पुनासा स्थित कृष्णा ज्वेलर्स पर 6-7 बदमाशों ने हथियार के बल पर धावा बोला था। बदमाश सोने-चांदी के आभूषणों से भरे दो बैग लूटकर फरार हो गए थे। वारदात के दौरान उन्होंने मारपीट और फायरिंग भी की थी।

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।

19 दिन तक पुलिस की 3 टीमों में शामिल 27 पुलिसकर्मियों ने आरोपियों की तलाश की। वारदात के तरीके के आधार पर 12 संगठित गिरोहों की पहचान की गई। जांच में पता चला कि झाबुआ की इसकरिया-रतन गैंगश् घटना के समय अपने क्षेत्र से गायब थी। इसके बाद पुलिस ने झाबुआ में गुप्त रूप से टीमें तैनात कीं। जैसे ही आरोपियों की गतिविधि का पता चला, पुलिस ने घेराबंदी कर तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सकरिया पिता झीतरा वसुनिया (46), रतन पिता नाहर उर्फ नारू (45) और विनोद पिता धन्ना उर्फ धनसिंह डामोर (34) के रूप में हुई है। ये सभी झाबुआ जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। इनके कब्जे से 500 ग्राम सोने के आभूषण और हथियार जब्त किए गए हैं।

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी आदतन और संगठित अंतरराज्यीय अपराधी हैं। इनके खिलाफ मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में हत्या, डकैती और लूट जैसे गंभीर अपराधों के एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। कार्रवाई में नर्मदानगर टीआई विकास खिंची और पुनासा चौकी प्रभारी राजेंद्र सय्यदे की अहम भूमिका रही। एसपी ने टीम को 10 हजार रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की है।

सर्व समाज का विरोधः यूजीसी के नए कानून के खिलाफ रैली प्रदर्शन

माही की गूंज, खरगोन।

सर्व समाज के 1000 से अधिक लोगों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए कानून के विरोध में रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने इसे श्काला कानून बताते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार को खुली चेतावनी दी कि यदि यह कानून वापस नहीं लिया गया, तो वे भारतीय जनता पार्टी के बजाय नोटा (मतदान के लिए कोई भी उम्मीदवार न चुनने का विकल्प) को वोट देंगे। रैली के बाद तहसीलदार दिनेश सोनरतिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

दोपहर 1 बजे राधा वल्लभ मार्केट स्थित परशुराम चौक से रैली शुरू हुई। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुराने कलेक्टर कार्यालय परिसर तक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष नारेबाजी करते हुए शामिल हुए। सभी ने एक सुर में कानून का विरोध किया।

सर्व समाज के प्रतिनिधि राजू शर्मा ने कहा कि एक ओर देश में जात-पात खत्म करने के लिए हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ऐसे काले कानून लाकर समाज में भेदभाव पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि ष्सरकार को गौ हत्या, धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ कानून लाना चाहिए था, न कि ऐसा कानून जो समाज को तोड़ने वाला हो।

प्रदर्शन में शामिल ममता जितेंद्रसिंह सोलंकी ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे कानून देश में सवर्णों के लिए जीवन मुश्किल बना रहे हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि ष्कहीं देश में सवर्णों की स्थिति बांग्लादेश में हिंदुओं जैसी न हो जाए।

कपास किसानों की समृद्धि के लिए मजदूर संघ और आईएलओ की चौपाल

माही की गूंज, अलीराजपुर।

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के संयुक्त तत्वावधान में, राईज फॉर इम्पैक्ट के सहयोग से अलीराजपुर जिले के ग्राम सेजा में कपास किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना एवं सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कपास की खेती को अधिक उन्नत बनाना और किसानों को सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ना था।

कार्यक्रम में अखिल भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरणमय पंडिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीकों और सही मार्गदर्शन से कपास की खेती न केवल लाभप्रद बनाई जा सकती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भी तैयार की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के प्रदेश महामंत्री कुलदीप गुर्जर ने किसानों को सरकारी योजनाओं की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कैसे किसान बिचौलियों से बचकर शासन की योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकते हैं और अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं।

बैठक में जानकारी दी गई कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) श्रमिकों और किसानों के उत्थान के लिए मुख्य रूप से पांच स्तंभों पर कार्य कर रहा है, जो सुरक्षा, न्यायोचित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर करते हैं।

कार्यक्रम का सफल संचालन जिला समन्वयक विवेक कुमार ने किया। सेजा ग्राम के सरपंच गिलडर डावर के सहयोग से आयोजित इस बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष उत्साहपूर्वक शामिल हुए।

फील्ड स्तर पर किसानों की सहायता के लिए 10 सदस्यीय टीम 5 ब्लॉकों में सक्रियता से कार्य कर रही है, जिसमें शामिल हैंरू सोमजी भूरिया (प्रदेश मंत्री, बीएमएस), राधु (राष्ट्रीय अध्यक्ष, वनवासी कृषि), धन सिंह कनेश (जिलामंत्री, बीएमएस), ऋतुराज लोहार, गिलदार भिंडे, रालू किराड़, गोविंद तोमर, नवल सिंह, विकेश, संगीता, पवन और शंकर डावर।

यह पहल अलीराजपुर के कपास उत्पादक किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतीय मजदूर संघ का लक्ष्य जिले के हर किसान को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाना है।

मासूम भतीजी से दुष्कर्म के बाद हत्या, सौतेला चाचा गिरफ्तार

माही की गूंज, बड़वानी।

जिला पुलिस ने सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए उसके सौतेले चाचा को बंदी बनाया है। पुलिस के अनुसार, मुखबिर की सूचना और तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर संदेही को हिरासत में लिया गया था। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को राजपुर थाना क्षेत्र के मुंडला ग्राम स्थित इंदिरा सागर नहर में बालिका का शव बरामद हुआ था। शव परीक्षण प्रतिवेदन में बालिका के शरीर पर दुष्कर्म और गंभीर चोटों के निशान पाए गए। प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट हुआ कि बालिका की मृत्यु पानी में डूबने के कारण हुई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जगदीश डावर ने एक विशेष दल का गठन किया था। परिजनों और साक्षियों के बयानों के आधार पर मृतका का चाचा संदेह के घेरे में आया। मनोवैज्ञानिक पद्धति से की गई पूछताछ में आरोपी ने बताया कि रविवार रात्रि लगभग 8 बजे जब परिवार के सदस्य सो रहे थे और बालिका के पिता सिंचाई हेतु खेत पर गए थे, तब उसने अपने सौतेले भाई की पुत्री का अपहरण किया। आरोपी बालिका को घर के पीछे नहर के समीप ले गया और उसके साथ कुकृत्य किया। जब बालिका रोने और चिल्लाने लगी, तो पकड़े जाने के भय से आरोपी ने उसे जान से मारने की नीयत से जीवित ही नहर में फेंक दिया था।

पुलिस ने इस जघन्य अपराध की आगे की जांच शुरू कर दी है, जिसमें पीड़ित के परिवार के सदस्यों और समुदाय से अधिक जानकारी इकट्ठा करना शामिल है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है कि जांच पूरी सटीकता और पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता के साथ की जाए। अधिकारी इस दुखद घटना के शिकार लोगों के लिए समर्थन और परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस घटना ने समुदाय को झकझोर कर रख दिया है और अधिकारियों ने निवासियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने का आग्रह किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

ट्रांसफर रोकने छात्रों ने निकाला 3 किमी पैदल मार्च

माही की गूंज, खरगोन।

जिले के सेगांव में बुधवार को एक शिक्षक के ट्रांसफर के विरोध में 200 से अधिक छात्र और अभिभावक सड़क पर उतर आए। सांदिपनी स्कूल के शिक्षक नटवर पाटीदार का अटैचमेंट रद्द कराने की मांग को लेकर वे ष्सर को वापस लाओष् के नारे लगाते हुए खरगोन कलेक्ट्रेट की ओर पैदल चल पड़े।

करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद डिप्टी कलेक्टर मौके पर पहुंचकर शिक्षक की वापसी का आश्वासन दिया, तब जाकर प्रदर्शन खत्म हुआ।

बुधवार दोपहर करीब 12 बजे विद्यार्थी और अभिभावक स्कूल से रवाना हुए। सेगांव से गुजरते समय तहसीलदार अंतर सिंह कनेश, पुलिस चौकी प्रभारी गजेंद्र चौहान और बीआरसी संदीप कापरनीस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। छात्र और अभिभावक अपनी मांग पर अड़े रहे और नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च जारी रखा।

अभिभावक कमल चौहान, अमित यादव, सुमित वर्मा और नानूराम यादव ने बताया कि सांदिपनी प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक नटवर पाटीदार का हाल ही में दशनावल के एक विद्यालय में अटैचमेंट कर दिया गया है। अभिभावकों का कहना था कि ष्शिक्षक पाटीदार बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे थे और वे उन्हीं शिक्षक को वापस चाहते हैं।ष् उन्होंने आरोप लगाया कि जनसुनवाई में भी उनकी बात नहीं सुनी गई।

देर रात पकड़ी गई पटाखा फैक्ट्री, आरोपी फरार

माही की गूंज, खंडवा।

देर रात पहली बार एक पटाखा फैक्ट्री पकड़ी गई। यह फैक्ट्री पड़ेला हनुमान मंदिर रोड पर सुनसान कॉलोनी, सम्यक गोल्ड के क्लब हाउस में संचालित हो रही थी। पुलिस की दबिश के दौरान आरोपी फरार हो गए। मौके से एक पिकअप वाहन, स्कूटर और 2 हजार किलो बारूद जब्त किया गया। पिकअप वाहन के संचालक अरबाज खान और उसके भाई बिलाल से पूछताछ की गई।

पुलिस ने बताया कि यदि यहां विस्फोट होता तो तीन किलोमीटर तक इसका असर पड़ सकता था। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने कहा कि मुख्य संदेही कांग्रेस नेता इमरान परयानी हैं। क्लब हाउस पर कब्जा कांग्रेस नेता यशवंत सिलावट का था, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया है।

सीएसपी अभिनव बारंगे ने बताया कि फैक्ट्री में 70 बोरे सुतली बम और 50-50 किलो सल्फर व एल्यूमीनियम पाउडर पाए गए। सुरक्षा व्यवस्था न होने की वजह से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास के सरकारी बंगले, कॉलोनी और सिहाड़ा ग्राम तक इसका असर पड़ सकता था।

केंद्रीय बजट का प्रचार-प्रसार करेगी भाजपा

माही की गूंज, खंडवा।

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक प्रचार-प्रसार की रणनीति बनाई है। इसके तहत प्रदेशभर के सभी जिलों में विशेष समितियों का गठन किया गया है, जो बजट में शामिल जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाएंगी।

भाजपा संगठन की ओर से नियुक्त इन समितियों में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल किए गए हैं। ये समितियां गांव-गांव, वार्ड स्तर पर बैठकें, संवाद कार्यक्रम और जनसंपर्क के माध्यम से केंद्र सरकार के बजट की प्रमुख विशेषताओं को जनता के सामने रखेंगी।

पार्टी नेतृत्व का कहना है कि बजट में किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। समितियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बजट से जुड़ी योजनाओं, कर में राहत और विकास से संबंधित प्रावधानों की सरल भाषा में जानकारी दें, ताकि आम नागरिक बजट के लाभों को समझ सकें।

खंडवा में केंद्रीय बजट के प्रचार-प्रसार के लिए 7 लोगों की समिति बनाई गई है। इस समिति का संयोजक जिला उपाध्यक्ष सुधांशु जैन को बनाया गया है। बाकी सदस्यों में जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी शामिल हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर ने बताया कि यह अभियान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा और इसमें अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

क्रिकेट को रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने दें

भारत-बांग्लादेश संबंधों के मौजूदा संकट में रोचक पहलू यह कि समाधान हेतु उपयुक्त तमाम घटक उसमें ही मौजूद हैं। भारत के लिए अवसर है कि नकारात्मक सोच वाले उन सभी विरोधियों की बाजी पलट दें जो 1971 के बाद से दो मुल्कों के बीच बेहद खास रिश्तों का पराभव चाहते हैं।

समाधान हेतु मुद्दों की सूची में शीर्ष पर क्रिकेट संकट है, जो एक पखवाड़े पहले हिंदू संगठनों द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग में बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान के खेलने पर रोक लगाने की मांग से पैदा हुई। बीसीसीआई इस मांग पर झुक गई और युवा मुस्तफिजुर को हटाया गया। इससे क्रोधित हुए बांग्लादेशियों का गुस्सा थम नहीं रहा है। उन्होंने टी-20 विश्व कप में भारत के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया है, जिसमें कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डंस स्टेडियम में होने वाला मैच भी एक है। उनकी मांग थी कि उनसे संबंधित क्रिकेट मैच, ठीक पाकिस्तान की तरह, तटस्थ देश श्रीलंका स्थानांतरित किया जाए।

फिर, यहां एक विचार है। संभवतः बांग्लादेश संबंधित मैचों को दक्षिण भारत में स्थानांतरित कर दिया जाता, जहां पर बंगाली दर्शक कम होते हैं। संभव है उन्हें अमिताव घोष द्वारा पिछले दशकों में, बहुत डूबकर लिखे तीन नॉवेल (द शैडो लाइन्स, द हंग्री टाइड, गन आइलैंड) के झकझोर देने वाले विषय-वस्तु का इतनी गहराई से अहसास न हो। अब शीर्ष भाजपा नेतृत्व के लिए समय आ गया है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) से राब्ता बनाएं -और बीएनपी भी यही करेद्ध हालांकि बीएनपी प्रमुख, तारिक रहमान, इन दिनों 12 फरवरी को होने वाले चुनावों की तैयारी के लिए रैलियों-बैठकों के साथ देश का तूफानी दौरा कर रहे हैं। आख़िरकार, यदि आरएसएस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से बात कर सकती है, तो शेष कुछ भी संभव है।

यह विचार दोनों पक्षों के लिए है कि अपना चेहरा बचाएं, ठंडे दिमाग वालों को वार्ता करने दें ताकि गर्म दल वाले अवसर हथिया न सकें। हमारे द्विपक्षीय इतिहास में इससे भी बदतर घटित हुआ है। वास्तव में, 1971 में बना उत्साह लंबे समय तक टिका नहीं; चार साल से भी कम अवधि में, 15 अगस्त, 1975 को, बांग्लादेशी फिर से बांग्लादेशियों का कत्ल कर रहे थे। वर्तमान में लौटते हुए। आज की कहानी अब मुस्तफिजुर रहमान और यहां तक कि उन शेख हसीना के बारे में और अधिक नहीं रही, जिन्होंने द प्रिंट को दिए अपने साक्षात्कार में आगामी बांग्लादेशी चुनावों में आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने को 'बदलाव का रूप धरा अधिनायकवाद' बताया है। यह तथ्य कि उन्होंने दिल्ली स्थित विदेशी संवाददाता क्लब को एक वॉयस मैसेज जारी किया है, उसमें भी मूल रूप से वही संदेश था। (ऐसा कहा जा रहा है कि उनका क्लब में खुद मौजूद न रहना या वीडियो संदेश जारी न करना, उनसे बनी सहमति का एक हिस्सा है)।

निस्संदेह, भारत-बांग्लादेश के बीच संबंध -अगस्त 2024 में हसीना के तख्ता पलट और हाल ही में बांग्लादेश में निर्दोष हिंदुओं की प्रतिशोध की भावना से की गई हत्याओं से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं- क्षति नियंत्रण तुरंत शुरू न करना बहुत नुकसानदायक होगा। एक शुरुआत हो चुकी है, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ढाका गए थे। पिछले नवंबर में बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान भारत में अपने समकक्ष अजीत डोभाल से मिलने दिल्ली आए थे।

दोनों तरफ दांव बहुत बड़ा लगा है। भारत को न केवल विभिन्न जनजातियों, धर्मों, कुलों और राजनीतिक दलों के मिश्रण वाले संवेदनशील उत्तर-पूर्व अंचल की सुरक्षा के लिए बल्कि पूर्वी दिशा के मुल्कों के साथ रिश्तों में हो रहे तेजी से बदलाव के बीच बांग्लादेश के साथ की जरूरत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि अगले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। कई लोग हसीना के अहंकार-कुशासन का हवाला देते हुए कहते कि उन्हें इसलिए उखाड़ फेंका गया। यह भी उतना ही सच है कि भारत ने बहुत कुछ नजरअंदाज किया, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि शेख हसीना और बीएनपी का आपस में हमेशा बैर रहा है। बीएनपी ने दो बार राष्ट्रीय चुनाव का बहिष्कार किया, जिससे घरेलू राजनीतिक कलह बढ़ गई।

लेकिन सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, शेख हसीना भारत की पसंदीदा क्यों बनी रहीं, इसका कारण यह है कि वे वास्तव में धर्मनिरपेक्ष रहीं। वे हिंदू अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने को महत्वपूर्ण समझती थीं, खुली वार्ता के अलावा सीमापारीय व्यापार के पक्ष में थीं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई के नेतृत्व वाले घातक लोगों को घुसने नहीं दिया। वे बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में किस कदर नुकसान पहुंचा सकते थे कि उसके सामने धुरंधर फिल्म में दिखाया गया कथानक दार्जिलिंग चाय और वॉटरक्रेस सैंडविच परोसने वाली किटी पार्टी की तरह लगता। उस विशाल हथियार जखीरे को कौन भूल सकता है जो संयोगवश तब मिला था जब तारिक की मां, दिवंगत खालिदा जिया प्रधानमंत्री थीं और जिसका उद्देश्य भारत के सात उत्तर-पूर्वी राज्यों में समस्या पैदा करना था?

आज की तारीख में शेख हसीना दिल्ली में हैं और भारत उन्हें कभी नहीं सौंपेगा दूइतनी बात बांग्लादेश को समझनी होगी। बल्कि सराहना भी करनी होगी कि भारत अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ता, चाहे दांव पर कुछ भी क्यों न हो। चाहे न्यायाधिकरण उन्हें सौंपने करने की मांग 'मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी' ठहराकर करें।

सबसे महत्वपूर्ण, दोनों देशों के कुलीन वर्ग को यह अहसास होना चाहिए कि आज का भारत और बांग्लादेश कहीं अधिक युवा, कहीं अधिक आकांक्षी और महत्वाकांक्षी हैं। करीब 63 प्रतिशत बांग्लादेशी और 52 प्रतिशत भारतीय 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। वे अतीत का कटु बोझ ढोना पसंद नहीं करेंगे। जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, उस वक्त तो वे पैदा भी नहीं हुए थे। वे जीवन में आगे बढ़ना और तरक्की करना चाहेंगे दृ न कि माथापच्ची में उलझे रहना।

ज्योति मल्होत्रा

तो फिर, आगे का रास्ता यह है कि हसीना के मामले को इतर रखा जाए। भारत में उनकी मौजूदगी से द्विपक्षीय संबंधों को दूषित न होने दिया जाए। नए बांग्लादेश को समझना चाहिए कि भारत का विशाल आकार और उपस्थिति उसको वह असाधारण फायदा पहुंचाती है, जिसका मध्य स्तर की शक्तियां केवल सपना देख सकती हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो बेगम खालिदा के पुत्र तारिक एक महीने से भी कम समय में बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री होंगे। कुल मिलाकर जयशंकर के साथ उनकी मुलाकात अच्छी रही। अब दोनों पक्षों के लिए लकीर पार करने का समय आ गया है।

सही मायने में आज बांग्लादेश को भारत की जरूरत कहीं ज्यादा है। हो सकता है शी जिनपिंग का चीन तारिक के लिए आर्थिक मदद का बड़ा चेक काटकर दे, जैसा कि जिनपिंग ने 2016 में शेख हसीना के वक्त भी किया था और पाकिस्तान बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ना शुरू कर दे। लेकिन सभी जानते हैं कि पाकिस्तान 2,000 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। उसकी अर्थव्यवस्था इतनी खस्ताहाल है कि उसने देश को चीन के हवाले कर रखा है। नैसर्गिक पड़ोसी भारत है। प्राकृतिक बाज़ार भारत है। स्वाभाविक साझेदार भी भारत है।

इसीलिए क्रिकेट नई शुरुआत करने का एक माध्यम बन सकता है। दोनों पक्षों के बीच तनाव को खत्म कर सकता है। लिट्टन दास का मिलन सूर्यकुमार यादव से होने दें। नागरिकों को खेलने दें।

एक-दूसरे को कबूल कर बने हमराह, 12 जोड़ां का सामुहिक निकाह सम्पन्न

माही की गूंज, जोबट।

अलीराजपुर स्थानीय दफ्तर दारुल क़जात की जैरे सरपरस्ती और आस्ताना-ए-होज उर्स कमेटी के तत्वावधान में पहली बार मुस्लिम समाज का सामूहिक निकाह आयोजित किया गया। जिसमे 12 जोड़ो का सामूहिक निकाह धार्मिक रीति-रिवाज़ो से सम्पन्न कराया गया। इस अवसर पर अलीराजपुर सहित आसपास के जिलों और गुजरात राज्य से बड़ी संख्या मे समाजजनो ने शिरकत कर दूल्हा-दुल्हन को अपनी दुआओं से नवाजकर खुशहाल जिंदगी की कामनाए की।

हजारों लोंग निकाह के गवाह बने

स्थानीय जामा मस्जिद चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम मे मप्र और गुजरात राज्य के 12 जोड़ो का सामूहिक निकाह सम्पन्न हुआ। सभी जोड़ो का वकीलों की वकालत ओर गवाहो की शहादत के बिच काजी साहब ओर ओलमाओ की निगरानी मे निकाह सम्पन्न कराएं गए, पश्चात कुतबा पढ़कर सुनाया गया। जिसके गवाह समाज के हजारों लोंग बने। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहर काजी अल्हाज सेय्यद अफ़ज़ल मियां, विशेष अतिथि सेय्यद आरिफ मियां, हाजी सेय्यद हनीफ मियां, हाजी सेय्यद जमालूद्दीन बाबा, सेय्यद रुकनुद्दीन बाबा, सेय्यद तन्वीर मियां, सेय्यद अबुल हसन बाबा, सेय्यद अशफाक मियां थे।कार्यक्रम मे अथितियों ने इज्तेमाई शादी की सराहना की ओर कमेटी और समाजजनो को मुबारक़बाद देते हुवे आयोजन की पैरवी करते हुवे शादियों मे फिजूल खर्च को रोकने हेतु नेक कदम और सामाजिक एकता बताई ।

दुल्हन पक्ष को घर गृहस्थी का उचित सामान प्रदान किया

इज्तेमाई शादी को लेकर समाजजनो मे व्यापक उत्साह देखा गया, समाज के बड़ी संख्या मे पुरुष, महिला ओर युवाजन सुबह से पहुँचना शुरू हो गए थे। सम्मेलन स्थल पर शामिल जोड़ो ओर समाजजनो के लिए अलग-अलग पांडाल बनाकर व्यवस्था की गईं थी, वाहनों के आवागमन ओर पार्किंग की भी माकूल व्यवस्था थी। सम्मेलन मे आये अतिथियों ओर समाजजनो ने दूल्हा-दुल्हनो को अपनी दुआओं से नवाज़ा। कार्यक्रम मे कमेटी सदर साजिद मकरानी सहित सदस्यों ने सेय्यदो सादातो का हार-फूल माला पहनाकर स्वागत किया। सम्मेलन मे सुबह सहभोज का आयोजन किया गया। वही कमेटी द्वारा समाजजनो के सहयोग से दुल्हन पक्ष को घर गृहस्थी का उचित सामान भी प्रदान किया गया था। दोपहर पश्चात् सभी दुल्हनो की बिदाई दी गईं। कार्यक्रम का संचालन शायर सिराज तन्हा और कयामुदिन क़याम ने किया एवं आभार कमेटी संरक्षक सेय्यद मोहसिन मियां ने माना। इज्तेमाई शादी के आयोजन को सफल बनाने मे विभिन्न संस्थाओ और कमेटियो सहित समाजजनो का सरहानीय योगदान रहा।

हरी सब्जियों की आड़ में ले जाई जा रही अवैध शराब जब्त

माही की गूंज, आलीराजपुर।

चांदपुर पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध बडी कार्यवाही की गई है। कार्यवाही मे पुलिस ने घेराबंदी कर एक महिंद्रा पिकअप वाहन से बडी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की है, जिसे सब्जियों के नीचे विशेष रूप से निर्मित गुप्त केबिन में छिपाकर ले जाया जा रहा था। थाना चाँदपुर पुलिस टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि अलीराजपुर की ओर से एक सफेद रंग की महिंद्रा पिकअप (क्रमांक गिजे-34-टी-3646) अवैध शराब लेकर चाँदपुर की ओर आ रही है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी के द्वारा टीम तैयार कर नाकेबंदी की कार्यवाही की गई। नाकेबंदी की कार्यवाही के दौरान ही एक संदिग्ध वाहन के आने पर उसे रोका गया। चालक ने अपना नाम गमजी पिता चुनिया वास्कले (निवासी ग्राम चौहजी) बताया। प्रारंभिक पूछताछ में चालक ने वाहन में हरी सब्जियां लदी होने की बात कहकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। संदेह होने पर जब वाहन को थाना परिसर में लाकर सूक्ष्मता से जांच की गई, तो सब्जियों के नीचे बॉडी में एक विशेष गुप्त बॉक्स (केबिन) बना हुआ पाया गया। बॉक्स खोलने पर उसमें से रॉयल चैलेंज व्हिस्की, किंगफिशर बियर, बडवाइजर बियर बरामद की गई।

आरोपी के पास शराब परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या परमिट नहीं पाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं 46 के तहत अपराध क्रमांक 10/2026 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी चाँदपुर उनि दिलीप चंदेल, सउनि मधुराजसिंह कुशवाह (कार्यवाही अधिकारी), सउनि रमेश अलावा, प्रआर गरवरसिंह नायक, प्रआर निलेश पाल, आर. सुनील, आर. धर्मेंद्र एवं आर. पुष्पेंद्र का योगदान रहा है।

खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026

माही की गूंज, आलीराजपुर।

खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 मध्य प्रदेश का ओलंपिक गेम में बालक-बालिकाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमे विजेता टीमों का जिला स्तर पर चयन हुआ। जिला स्तर से संभाग स्तर पर बालकों की टीम में रविंद्र पिता कमला मेंढा छारवी, कन्हैया डाबर बावड़ी, सावन पिता शेर सिंह कनेशबावड़ी, रोहित पिता उदय सिंह बघेल फुटतलाब, रंगो पिता धुनधर सिंह मेड़ा छोटी जुवारी, सुजल पिता मिथुन गुजराती, चित्रांश पिता मनोज वर्मा उदयगढ़, आशीष पिता भवान सिंह वास्केला छारवी, विशाल पिता बादल भूरिया छोटी जुवारी, कृपाल पिता मोहन सेन, उदयगढ़ इन बच्चों ने विकासखंड स्तर से लेकर जिला स्तर जिला स्तर से संभाग स्तर पर पहुंचे। वहां जाकर इन्होंने इंदौर संभाग लेवल पर बालक की टीम ने पहला मैच जीत कर दूसरा और तीसरा मैच हार गए, इस प्रकार संभाग स्तर से वापस लौटी। वहीं बालिकाओं ने विकासखंड स्तर से लेकर प्रथम स्थान जिला स्तर पर प्रथम स्थान संभाग लेवल पर प्रथम स्थान और राज्य स्टारी पर आज राज्य स्तरीय खेल का प्रदर्शन करेगी। यह सभी कस्तूरबा वन कन्या आश्रम की बालिकाएं है।

बालिकाओं की टीम इस प्रकार रही

कुमारी कृपा प्रकाश रावत, कुमारी कविता रहजिया नरगावा, कुमारी रंजना जाम सिंह चौहान ,कुमारी रवीना अनं सिंह वसुनिया, सुमित्रा अजमेर सिंह रावत, रंजना मुकेश बघेल, सजनी भारत सिंह रावत, टीनू बिलाम बामनिया आदि। अंतर्राष्ट्रीय रस्साकशी खिलाड़ी कोच जितेंद्र गुजराती के अथक प्रयासों से अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ विकासखंड से एक टीम बालिकाओं की राज्य स्तर पर खेलो एमपी यूथ गेम्स 2026 मध्य प्रदेश का ओलंपिक में हिस्सा लेगी।

क्षेत्र में धूम धाम से मनाई गणतंत्र दिवस की 77 वीं वर्षगांठ

माही की गूंज, आम्बुआ।

भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह क्षेत्र में विभिन्न आयोजनों के साथ धूम धाम से मनाये जाने के समाचार है, जिसमें ध्वजारोहण के बाद विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए बाल कलाकारों को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

आम्बुआ तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों एवं निजी तथा शासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं अन्य शासकीय अर्ध शासकीय विभागों में ध्वजारोहण किया गया। स्कूली बच्चों ने क़स्बे में राष्ट्रीय गीतों तथा नारों के साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लेकर प्रभातफेरी निकाली तथा सार्वजनिक रूप से पंचायत प्रांगण में आयोजित झंडा बंधन में सम्मिलित हुए। जहां पर सरपंच रमेश रावत ने साथी उपसरपंच थानसिंह भयडिया के साथ ध्वजारोहण किया। बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिन्हें प्रोत्साहन हेतु दर्शकों ने तथा जनप्रतिनिधियों ने नगद पुरस्कार से नवाजा।

कार्यक्रम के पूर्व पीएम श्री उ मा वि आम्बुआ में प्रभारी प्राचार्य लोंगसिंह भयडिया, पुलिस थाने पर थाना प्रभारी मोहन सिंह डावर, बालक/कन्या प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक मुकाम सिंह डुडवे, आदिमजाति सहकारी समिति में प्रबंधक डी एस भयडिया, मां पार्वती मेमोरियल स्कूल में संचालिका मनोरमा माहेश्वरी, एवं अंशुल विद्या मंदिर में रमीला अगाल, स्वास्थ्य केंद्र में प्रमिला सोलंकी, बोहरा

मस्जिद प्रांगण में वाली मुल्ला शब्बीर भाई, मां शारदा पेट्रोल पंप पर सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक करणसिंह रावत के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायतों में सरपंचों एवं शिक्षण संस्थाओं में संस्था प्रधानों ने ध्वजारोहण किया,इस अवसर पर पंचायतों के उपसरपंच, पंच, सचिव जनप्रतिनिधि पत्रकार आदि उपस्थित रहे।

स्लम बस्तियों में पीने लायक नहीं पानी

माही की गूंज, धार।

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से 28 लोगों की मौत के बाद जहां प्रशासन पेयजल की गुणवत्ता को लेकर सतर्कता का दावा कर रहा है, वहीं धार नगर पालिका क्षेत्र की स्लम बस्तियों में लापरवाही की गंभीर तस्वीर सामने आई है। अमृत 2.0 योजना के तहत की गई पेयजल सैम्पलिंग में शहर की कई स्लम बस्तियों में पानी पीने योग्य नहीं पाया गया, बावजूद इसके सुधार के लिए न तो रिपोर्ट संबंधित शाखा तक पहुंची और न ही कोई ठोस कार्रवाई की गई। मायापुरी, ब्रह्माकुंडी, अर्जुन कॉलोनी सहित कई स्लम एरियों में नलों से लिए गए पानी की जांच में पीएच मान 10 से 13 तक पाया गया है, जबकि टीडीएस भी साढ़े 300 से साढ़े 500 के बीच दर्ज हुआ। यह दोनों ही मानक शासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह का पानी लंबे समय तक पीने से पाचन तंत्र सहित अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह सैम्पलिंग मई-जून 2025 में की गई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट आज तक नगर पालिका की जल शाखा में नहीं सौंपी गई।

स्वसहायता समूहों ने की जांच, विभाग तक नहीं पहुंची रिपोर्ट

नगर पालिका ने अमृत 2.0 योजना के तहत जल प्रहरी नियुक्त किए हैं, जिनकी जिम्मेदारी स्वसहायता समूह की महिलाओं को सौंपी गई है। इन्हें जल परीक्षण किट उपलब्ध कराई गई और प्रशिक्षण भी दिया गया। सहज और दृष्टि स्वसहायता समूह की महिलाओं ने अब तक शहर के करीब 2 हजार नलों से पानी के सैम्पल लेकर जांच की है। प्रति सैम्पल 48 रुपए का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन बीते आठ महीनों से यह पूरी रिपोर्ट नगर पालिका की जल शाखा तक नहीं पहुंच पाई। इस स्थिति ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि जांच हो रही है, लेकिन नतीजों पर कार्रवाई नहीं हो रही, तो सैम्पलिंग का औचित्य ही सवालों के घेरे में है।

टेस्टिंग प्रक्रिया पर भी सवाल, जिला लैब ने जताई आपत्ति

स्लम बस्तियों में अत्यधिक पीएच मान सामने आने के बाद टेस्टिंग प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लग गए हैं। जिला जल प्रयोगशाला के सीनियर केमिस्ट पवित्रम ने इतना अधिक पीएच मान आने की संभावना पर ही सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पीएच का मान 10 से 13 होना सामान्य स्थिति में संभव नहीं है और इसमें टेस्टिंग की कसावट व निगरानी जरूरी है। मानकों के अनुसार पेयजल का पीएच 6.5 से 8.5 और टीडीएस 100 से 300 एमजी के बीच होना चाहिए। रिपोर्ट में जहां पीएच अत्यधिक है, वहीं टीडीएस भी कई क्षेत्रों में मानक से अधिक पाया गया है। इन हालात में पानी को सुरक्षित नहीं माना जा सकता।

जनसेवा संकल्प के तहत टैंकर वितरण

माही की गूंज, जोबट।

जोबट विधायक सेना महेश पटेल द्वारा कोटबू, खंडाला, पलासदा, चिचलाना एवं झोरा ग्रामों में टैंकर वितरण किया भीषण गर्मी में पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई। कार्यक्रम स्थल पर कार्यकर्ताओं ने विधायक का फूलमालाओं एवं ढोल-धमाकों के साथ स्वागत किया। टैंकर उपलब्ध होने से ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया। इस दौरान विधायक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि टैंकर का पानी किसी एक घर पर न रखा जाए, बल्कि सभी ग्रामीणों को समान रूप से पानी उपलब्ध कराया जाए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सेना महेश पटेल ने कहा, आप सबके सहयोग और मेहनत से मैं जीतकर आई हूँ। मैं सतत रूप से क्षेत्र में विकास कार्य कर रही हूँ। कहीं हैंडपंप, कहीं सड़क, कहीं टैंकर, तो कहीं बिजली की व्यवस्था कराई जा रही है। किसी का काम आगे होगा, किसी का पीछे, पर सबका काम किया जाएगा। मैं जो वादा करती हूँ, उसे निभाती हूँ और काम करके दिखाती हूँ।

इस दौरान ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए, जिस पर विधायक ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। विधायक ने कार्यकर्ताओं को उनके क्षेत्रों में कराए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी भी दी।

साथ ही कार्यकर्ता संवाद मनरेगा बचाओ विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीब परिवारों की जीवनरेखा है और इसे कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वे ग्रामीणों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें। उन्होंने बताया कि, आज आलीराजपुर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, संवाद और विकास पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

ओलावृष्टि से फसल खराब, किसान ने दी जान

माही की गूंज, उज्जैन।

जिले तराना में ओलावृष्टि से फसल बर्बाद होने पर एक किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत से पहले किसान ने अपनी बर्बाद फसल का वीडियो दर्दभरे गीत के साथ स्टेटस पर डालकर रिश्तेदार से बात की थी। दो दिन पहले उसकी बहन की सगाई हुई थी, अप्रैल में उसकी शादी होने वाली थी।

शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर तराना तहसील के ग्राम खेड़ा जामुनिया में रहने वाले किसान पंकज मालवीय (30) ने अपने छह बीघा खेत में गेहूं की फसल बोई थी। मंगलवार शाम को आंधी के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से पूरी फसल खराब हो गई। इससे आहत होकर पंकज रात को घर नहीं गया। बुधवार सुबह जब परिजन खेत पर पहुंचे तो वह फांसी के फंदे पर लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की बात कही है।

पिता की पहले ही हो चुकी है मौत

बताया गया कि पंकज के दो बच्चे हैं, एक आठ साल का बेटा और पांच साल की बेटी। उसकी दो बहनें हैं, जबकि पिता की पहले ही मौत हो चुकी है। पंकज ही घर का अकेला कमाने वाला था। फसल चौपट होने से वह गहरे तनाव में था. उसने मरने से पहले दर्दभरे गीत 'ऐसा क्या गुनाह किया...' पर अपनी खराब फसलों का वीडियो स्टेटस पर लगाया था।

बहन की शादी को लेकर था चिंतित

रिश्तेदार ईश्वर लाल परमार ने बताया कि दो दिन पहले पंकज की बहन की सगाई हुई थी। अप्रैल में शादी होनी है। ओलावृष्टि के बाद शाम करीब सात बजे पंकज ने फोन कर बहनों की शादी को लेकर चिंता जाहिर की थी। उसने कहा था कि फसल बर्बाद हो गई है, अब शादी कैसे होगी। समझाने के बावजूद उसने यह कदम उठा लिया।

विधायक ने की 50 लाख के मुआवजे की मांग

किसान की मौत के बाद विधायक महेश परमार परिजनों को सांत्वना देने उसके घर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फसल बर्बाद होने के चलते किसान ने आत्महत्या की है। उन्होंने कहा कि किसान के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। जिससे परिवार की आर्थिक मदद हो सके।

सहयोग गार्डन में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन संपन्न

माही की गूंज, आलीराजपुर।

वरिष्ठ नेता स्वर्गीय दिनेश हरसोला व ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ स्वर्गीय अश्विनीकुमार पंचोली की स्मृति में पर्यावरण सहयोग संस्था और श्री कृष्ण हास्पिटल करमसद गुजरात के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन एक फरवरी रविवार को स्थानीय सहयोग गार्डन में होगा। सहयोग संस्था के मीडिया प्रभारी कृष्णकांत बेड़िया ने बताया कि, शिविर का समय प्रातः 9 बजे से सायंकाल 5 बजे तक रहेगा। स्वास्थ्य शिविर में वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। जिसमें अस्थि रोग, स्त्री रोग, चर्म रोग, नाक कान गले के रोग, नेत्र रोग, सर्जरी, बाल रोग आदि के विशेषज्ञ चिकित्यक अपनी सेवाएं देंगे। इसीजी एवं दवाईयां निःशुल्क रहेगी। खून की जांच व एक्सरे नाम मात्र की दर पर किया जाएगा। बेड़िया ने बताया कि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के लिए संबंधित मरीज व नागरिक अपना पंजीयन सहयोग संस्था अध्यक्ष राजीव शाह अन्य पदाधिकारी आशुतोष पंचोली, दीपक दीक्षित, राकेश चौहान, कैलाश कमेड़िया, डॉ शकील शेख, जिगेश कोठारी, अनवर भाई दबुक आदि के मोबाईल पर संपर्क कर करवा सकते हैं।

ज्ञात रहे कि श्री कृष्ण हास्पिटल करमसद जिला आणंद गुजरात की ओर से जिला मुख्यालय पर दूसरी बार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। उक्त अस्पताल में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध है। सहयोग संस्था ने इस शिविर में जरुरत मंद आम नागरिकों से अपना निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराने की अपील की है।

गौ-हत्या का विरोधः सर्व हिन्दु समाज का प्रभावी प्रदर्शन, लेकिन असमंजस की स्थिति में जिला आधा खुला आधा बंद

प्रदर्शन से भाजपा नेताओं की दूरी बनी बहस का मुद्दा तो कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया ने पहुंचकर दिया समर्थन

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले में 6 दिसम्बर को सजेली नानियासाथ में उजागर हुए गौहत्या कांड को लगभग डेढ़ माह से अधिक हो गया था। इस पूरे समय में इस पूरे गौहत्या मामले में किसी तरह का कोई बड़ा आंदोलन ना होने पर सवाल खड़े हो रहे थे। पुलिस भी अपनी रेंगती रफ्तार में कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इस मुद्दे पर जैसे -जैसे लोगों में आक्रोश बड़ा पुलिस की कार्रवाई में भी तेजी देखने को मिली। मगर पुलिस की इस कार्रवाई से असंतुष्ट हुए लोगों ने आखिरकार बड़े आंदोलन व धरना प्रदर्शन का मन बना लिया। जब यह खबर सरकारी गलियारों में आग की तरह फैली तो प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गए और आंदोलन व प्रदर्शन के पहले ही सजेली नानियासाथ के जंगलों की खाक छानने फिर से निकल पड़ी। गौकशी वाले स्थान व आसपास के जंगल में फिर से अतिक्रमण मुहिम चलाई गई। कई शासकीय जमीनों को अतिक्रमण मुक्त भी कराया गया। आंदोलन के तुरंत पहले हुई इस प्रशासनिक कार्रवाई को अब लोग उल्टे चश्मे से देख रहे है। लोगों का कहना है कि, जब जिला प्रशासन को इस बात का अंदाजा हुआ कि, अब बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन होने वाला है तो लोगों के आक्रोश को ठंडा करने के लिए आंदोलन व प्रदर्शन के पहले ही प्रशासन व पुलिस हरकत में आ गई। बावजूद इसके जिले के सर्वहिन्दु समाज ने इस आंदोलन व प्रदर्शन को गंभीरता से अंजाम दिया।

हालांकि घटना के लगभग डेढ़ माह बाद हुए इस आंदोलन में भी असमंजस की स्थितियां पैदा होती देखी गई। मेघनगर ब्लॉक के सजेली नानियासाथ गांव में हुए गौ-हत्या कांड को लेकर पहले विश्व हिंदू परिषद व सर्व हिन्दु समाज की ओर से यह ऐलान हुआ कि, 27 जनवरी को गौहत्या कांड के विरोध में पूरा जिला बंद रहेगा और पूरे जिले का सर्वहिन्दु समाज जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन और पुलिस को ज्ञापन सौंपेगा। फिर 25 जनवरी रात को एक सूचना निकलकर सामने आने लगी कि, 27 जनवरी को जिला बंद व प्रदर्शन निरस्त किया जाता है। इस सूचना के वायरल होते ही जिले में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि, आखिर ऐसा हुआ क्यों...? 27 जनवरी के आंदोलन व प्रदर्शन के निरस्त होने पर माहौल गर्मा गया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस चल पड़ी। नतीजा यह निकल कर सामने आया कि 26 जनवरी को फिर एक सूचना व संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा वक्तव्य जारी किए गए कि, 27 जनवरी को गौ-हत्या के विरोध में होने वाला जिला बंद व प्रदर्शन यथावत रहेगा। पदाधिकारियों ने अपने वक्तव्यों में कहा कि, यह किसी संगठन का आयोजन नही है, यह तो जिले के सर्व हिन्दु समाज द्वारा किया जा रहा आंदोलन व विरोध प्रदर्शन है, यह आयोजन यथावत रहेगा।

इस तमाम गहमा-गहमी के बीच 27 जनवरी को सर्व हिन्दु समाज द्वारा किया गया आंदोलन व प्रदर्शन सफल तो रहा लेकिन संपूर्ण जिला बंद को लेकर असमंजस वाली स्थिति दिखाई दी। जिले के थांदला, मेघनगर, काकनवानी आदि कई कस्बों में इसका असर देखने को मिला तो कई कस्बें इसके पूर्णतः खुले दिखे। जहां बंद का असर दिखा वहां व्यापारियों ने अपनी स्वेच्छा से इसे समर्थन देते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। तो कई कस्बों में बाजार रोजाना की तरह की खुले दिखाई दिए। जिले की पेटलावद विधानसभा में इस आंदोलन का कोई असर देखने को नहीं मिला तो थांदला, मेघनगर और झाबुआ में इस आंदोलन को भरपूर समर्थन मिला।

भाजपा के नेता रहे नदारत, वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया ने दिया सकल हिन्दु प्रदर्शन को समर्थन और कहा मैं भी हिन्दु हूँ।

27 जनवरी को जिला मुख्यालय के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में सुबह 11 बजे से ही जिले के अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आना शुरू हो गए थे। 12 बजे तक उत्कृष्ट विद्यालय का यह मैदान काफी हद तक भर चुका था। इसके बाद एकत्रित हुई भीड़ को वक्ताओं ने सम्बोधित किया। यहां एक बार फिर स्थिति असमंजस वाली देखने को मिली। आयोजन कर्ताओं में ही तालमेल दिखाई नहीं दिया। उत्कृष्ट मैदान पर इकट्ठा हुई भीड़ को देखते हुए आयोजन का हिस्सा रहे विहिप के क्षेत्रीय गौ-रक्षा प्रमुख ने ज्ञापन लेने के लिए प्रशासन को वहीं बुला लिया। जब यह खबर अन्य पदाधिकारियों को लगी तो बीच आयोजन में ही खींचतान की स्थिति निर्मित हो गई। अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बात पर अड़ गए कि, रैली निकालकर कलेक्ट्रोरेट पहुंचकर ज्ञापन देंगे। इसी खींचतान के बीच अपर कलेक्टर धरना स्थल पर पहुंच गए और ज्ञापन स्वीकार भी कर लिया। इसे लेकर अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विरोध भी जताया। माहौल को खराब होता देख आखिरकार शीर्ष नेतृत्व को झुकना पड़ा और यह तय हुआ कि, रैली निकालकर दूसरा ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिसके बाद धरना स्थल से इकट्ठी हुई भीड़ रैली के रूप में मुख्य बाजार से होती हुई कलेक्ट्रोरेट पहुंची और एसपी व एसडीएम को ज्ञापन देकर न्यायिक जांच आयोग गठित करने की मांग करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही गौ-हत्या के विरूद्ध अधिनियम बनाए जाने की मांग भी की गई। ।

इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि, सर्व हिन्दु समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से भाजपा के तमाम बड़े नेता व जनप्रतिनिधियों ने बहुत ही दूरी बनाए रखी। धरना प्रदर्शन में भाजपा के कुछ छोटे-मोटे नेता जरूर दिखाई दिए लेकिन भाजपा का कोई भी बड़ा चेहरा इस आंदोलन में शामिल नहीं रहा। इसके उलट कांग्रेसी खेमें से कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया व उनके समर्थकों ने सकल हिन्दु समाज के इस धरना आंदोलन व बंद को धरना स्थल पर पहुंचकर व रैली में शामिल होकर समर्थन दिया। कांतिलाल भूरिया के साथ जिला कांग्रेस के निर्मल मेहता, जितेन्द्रसिंह राठौर सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कांतिलाल भूरिया व कांग्रेसियों के इस तरह सर्व हिन्दु समाज के इस आंदोलन में पहुंचने पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। लोग अपने-अपने स्तर पर कई तरह की चर्चाएं करते नजर आए। लोगों का कहना था कि, यह बड़ी विडम्बना है कि, देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लोकसभा सीट पर भाजपा का सांसद है, 3 मंत्री है, बड़ी पहुंच रखने वाले भाजपा के बहुत से नेता है, मगर जिले के इस आंदोलन में आने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। यह कई तरह के सवाल पैदा करता है। वहीं दूसरी ओर कांतिलाल भूरिया है जो कांग्रेस के नेता है और फिलहाल कांग्रेस देश व प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में है, तो कांतिलाल का इस तरह सकल हिन्दु समाज के आंदोलन में पहुंचना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। लोगों का कहना है कि, कांतिलाल ने इस आयोजन में पहुंच कर नेहले पर देहला दे दिया है। वे, हो सकता है इस आयोजन के जरिए अपने राजनीतिक जीवन की पतवार संभालने की कोशिश कर रहे हों। चाहे जो हो लेकिन यह एक बड़ा पहलु है कि, सर्व हिन्दु समाज के इस आयोजन से भाजपा ने दूरी बनाई तो कांग्रेसियों ने इसे सीधे तौर पर खुला समर्थन दे दिया है।

प्रशासन पर लगे बाजार खुलवाने के आरोप

इस पूरे घटनाक्रम में यह बंद प्रशासनिक कार्रवाई से असंतोष के चलते आहुत किया गया था। हिंदू संगठनों के इस बंद से प्रशासन के हाथ?-पांव फूलने लगे थे। जिसको लेकर प्रशासन ने मीडिया के माध्यम से अब तक कि की गई कार्रवाइयों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। तो वहीं जिले के समस्त गांवों में चौपाल लगा कर गो-वंश की महत्ता और गो-वंश हत्या से संबंधित कानूनों की जानकारी ग्रामीणों को देने के अभियान की जानकारी भी सामने आई। तो वहीं कुछ समाचार पत्रों में बंद निरस्त किए जाने संबंधी समाचार भी प्रकाशित हुए। इससे जिले भर में बंद को लेकर असमंजस पैदा हुआ। जिसके बाद विहिप और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर बंद यथावत रहने का आव्हान किया। इस असमंजस के चलते जिले के कई कस्बे खुले रहै। तो वहीं थांदला में सफल बंद के बाद प्रशासन ने पुलिस वाहन से मुनादी करवाकर व्यावसायियों से दुकानें खोलने का आव्हान किया। ?ज्ञापन के दौरान कार्यकर्ताओं ने झाबुआ में पुलिस द्वारा जबरन दुकानें खुलवाने के आरोप तक लगाए।

अपराधियों व माफियाओं को साहूकार और साहूकार को अपराधी बनाने का राष्ट्रपति सम्मान पत्र देना चाहिए जिले की पुलिस को

माही की गूंज, खवासा।

कहावत है चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए उक्त लोकोक्ति झाबुआ जिले की पुलिस पर हमेशा चरितार्थ होती है। इसलिए एमपी पुलिस की अजब कहानीया अक्सर सामने आती है। जिसमें पुलिस लूट को चोरी की घटना बता देती है। चोरी की घटनाए हो तो मामला दर्ज न कर उन्हें साहूकार बना देती है। वहीं झाबुआ जिले में शराब माफियाओं को साहूकार बनाकर शिकायत कर्ताओ पर मामला दर्ज कर लेती है। तो कई बार शराब माफियाओं के अवैध शराब से भरे वाहन चौकी-थानो पर जाने के बाद भी शराब से भरे वाहन बिना प्रकरण के साठ-गांठ कर छोड़ दिए जाते हैं। वहीं जब कहीं सरकार की योजनाओं में अनियमित्ताएं व लोगों से ठगी की जाती है तो अगर उस ठगी को जो साहूकार उजागर करता है उस साहूकार को पुलिस अपराधी बना देती है। चाहे खाद में लगी भीड़ में कोई बीमार हो जाए या आधार सेंटर पर लोगों को आधार करेक्शन के नाम पर नियमित ठगी की जाए और वह समाचार पत्रों में उजागर हो तो ऐसे में भी प्रशासन समाचार पत्रों में प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को अपराधी बना देते हैं और अनियमित्ताएं व ठगी करने वाले को फरियादी बनाकर साहूकार से अलंकृत पुलिस कर देती है। अगर इन अनियमिताओं को कोई पत्रकार प्रकाशित करता है तो उन पत्रकारों को पुलिस व्यक्तिगत रूप से अपना विरोधी भी मान लेती है और जनप्रतिनिधि भी यह तमाशा अक्सर देखते हैं। ऐसे में अगर पुलिस का यह कृत्य अपराध योग्य नहीं है तो तय है पुलिस के यह कृत्यो को अब सम्मान योग्य ही माना जाना चाहिए...! तथा इस तरह के जो कृत्य पुलिस अधिकारी जितना अधिक करता है उसे उतना बड़ा सम्मान देना चाहिए। इसलिए अब लोग चर्चाओं में कहने लगे हैं कि, पुलिस की अपने उपरोक्त मनमानी अपराधियों व माफियाओं को साहूकार और साहूकार को अपराधी बनाने का मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक का सम्मान देकर झाबुआ जिले की पुलिस को नवाजा जाना चाहिए।

चोरी का प्रयास में तीन चोर ग्रामीणों ने पकड़े पर चौथे का खुलासा आज तक नहीं करपाई पुलिस

खवासा चौकी के अंतर्गत दो मामले सामने आए जिसमे पहला गुरुवार-शुक्रवार रात्रि में ग्राम पाटडी में चार चोर सेंध लगाकर ग्राम में चोरी करने का प्रयास कर रहे थे जिसकी भनक ग्राम के किसी व्यक्ति को लगी। और एक-एक को फोन से सूचना कर चोरो की रैकी की। चारों चोरों ने राजू पिता दिता निवासी पाटडी के घर में सेंध लगाई और चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। उसी समय ग्रामीणों ने सेंध लगाकर चोरी करने वाले चोरों को पकड़ने का प्रयास किया तो चारों चोर ग्रामीणों को चकमा देकर भागने का प्रयास किया।

ग्रामीणों ने पिछाकर तीन चोरो को पकड़ने में सफलता हासिल की और एक चोर भागने में सफल रहा। गुस्साए ग्रामीणों ने चोरो को जमकर पीटा भी और खवासा पुलिस को रात्रि में सुपुर्द कर दिया।

पुलिस ने तीनों चोरो के विरुद्ध ग्रामीणों के दबाव के चलते बीएनएस की धारा 303(2), 305, 62 के तहत मामला दर्ज कर बिना पीआर मांगे न्यायालय में मेडिकल करवाकर पेश कर दिया और न्यायालय ने चोरो को जेल भेज दिया।

वही खवासा पुलिस 5 दिन के बाद भी चौथे चोर तक पहुंचने में नाकाम रही। समाचार लिखने के पूर्व बुधवार को पुलिस से जानकारी ली तो बताया, चोरों की न्यायालय से पीआर नहीं मांगी थी, ग्रामीणों ने उन्हें पीटा था मेडिकल करवाकर थांदला न्यायालय में पेश कर दिया। चौथे चोर के संबंध में पांच दिन के बाद भी पुलिस कहती है चोर का नाम नहीं मालूम है, यानी कि पुलिस उस चोर तक पहुंचना ही नहीं चाहती यह स्पष्ट होता है। क्योंकि तीन चोर ग्रामीणों के माध्यम से पुलिस को थाल में परोसे हुए मिले उसके बावजूद भी उन चोरों से चौथे चोर का नाम पुलिस नहीं ले सकी। इसे पुलिस की विफलता कहे या पुलिस की चल रही अपनी कार्यप्रणाली के तहत चौथे चोर को संरक्षण देकर अपराधी को अपराध से मुक्त रखना चाहती है यह तो पुलिस ही जाने। लेकिन लोगो का कहना है, अगर चोर चोरी करने में सफल होकर रफू-चक्कर हो जाते और पुलिस को मामला दर्ज करवाते तो पुलिस मामला दर्ज करती ही नहीं। ऐसी कई क्षेत्र में चोरियां हो चुकी है जिसका मामला आज तक पुलिस ने दर्ज नहीं किया और न ही कभी चोरो तक पुलिस पहुंच पाई।

ग्रामीणो ने 3 चोर को पुलिस के सुपुर्द किया लेकिन पुलिस चौथे चोर का नाम तक पता नही कर पाई।

अवैध शराब से भरी जिप लोगो ने घेर रखी जो पुलिस चौकी खवासा पहुची पर बिना कार्रवाई मामला रफा-दफा।

कुछ समय पूर्व ही उमरीपाड़ा व धूमडिया में खुले आम लुटेरो ने लूट को अंजाम दिया पर खवासा-थांदला पुलिस की कारस्तानी में लूट को चोरी बताकर दोनों लूट का पटाक्षेप कर दिया। ऐसे में साफ है कि, पुलिस चोरो को संरक्षण दे रही है और अपराधों को बढ़ावा।

शराब से भरी जीप जाम में फसी, विवाद हुआ जिप चौकी तक पहुंची पर पुलिस का संरक्षण ऐसा कि मामला पूरा की पूरा रफा दफा

थांदला-खवासा पुलिस की तारीफ़ जितनी करें शायद उतनी ही कम है, क्योंकि यह पुलिस मरे हुए व्यक्ति तक को जिंदा बताकर मुख्य आरोपी बना देती है और जिंदी महिला को मरी हुई बताकर बेगुनाह को गुनेहगार बनाने वाली पुलिस कुछ भी चमत्कार कर सकती है।

जिसका एक और चमत्कार मंगलवार को भी खवासा में देखा गया। मामला यह कि, थांदला से खवासा की और अवैध शराब से भरी एक बोलेरो जीप आ रही थी कि, सड़क निर्माण के चलते सिंगल पट्टी रोड पर वाहनों की आवाजाही में जाम में फंस गई। वहीं पाटड़ी का एक युवक के दो पहिया वाहन से उक्त शराब से भरी जीप जाम में आगे लेते समय अड़ गई। जिसके बाद बाइक चालक ने शराब से भरी जीप चालक से विवाद हो गया और बोलचाल में विवाद इतना बढ़ गया कि, देखते ही देखते लोगों की बड़ी भीड़ लग गई और जाम लग गया। लोगों ने जीप के अंदर देखा तो शराब भरी हुई थी। उक्त बात खवासा के एक युवक को पता लगी जो कि, खुद खवासा में अवैध शराब विक्रय के अवैध अड्डे एक से अधिक संचालित अपने पिता के साथ करता है। उक्त युवक मौके पर पहुंचा और अपना रुतबा झाड़ लोगों को कहने लगा कि, यह शराब की गाड़ी मेरी है, मेरे यहां आ रही थी।

बाइक चालक व उसके समर्थक लोगों को युवक की बात पर और गुस्सा आ गया और पुलिस को सूचना देकर उक्त वाहन पुलिस चौकी पर ले जाया गया। जिसका प्रूफ खवासा चौकी में लगे सीसीटीवी कैमरे भी कर सकते हैं। शराब से भरी जीप चौकी पर जाने के बाद लोगों की भीड़ खत्म होते ही शराब कंपनी के कर्मचारी खवासा चौकी पर पहुंचे और दो पहिया वाहन मालिक पाटड़ी निवासी व शराब कंपनी के बीच खवासा पुलिस की उपस्थिति में चौकी पर सुलह करवा दी। और शराब माफिया को अपना आका मानने वाली पुलिस ने शराब माफिया का निर्देश मान सार्वजनिक रूप से अवैध शराब से भरी जीप चौकी पर जाने के बाद भी पुलिस ने बिना किसी कायमी के छोड़ दी।

मामले में जब बुधवार को खवासा पुलिस से चर्चा की तो, मौके पर ही बाइक चालक से सुलह होने की बात पुलिस कहने लगी। साहब, गाड़ी चौकी पर लाए थे न, तो हंसते हुए साहब बोले मामले में सुलह हो गई और फोन काट दिया।

अब चर्चा होने लगी कि, शराब से भरी गाड़ी को चौकी से लाने में दो पहिया वाहन से सुलह करवाने में जो दिए होंगे वह आज की कीमत से 50 ग्राम चांदी भर खरीद सकता है दिए होंगे। लेकिन पुलिस चौकी पर शराब से भरी जीप आने के बाद छोड़ने के बदले नियमित बंदी के बाद भी एक किलो से अधिक चांदी खरीद सकते हैं के मूल्य की चांदी पुलिस ने अवश्य काटी होगी। ऐसी उपरोक्त कारस्तानिया करने वाली पुलिस का कोई अपराध नहीं माना जाता है। तो क्यों न अपराधियों व माफियाओं को साहूकार और साहूकार को अपराधी बनाने का किर्तीमान सम्मान-पत्र मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को झाबुआ जिले की पुलिस को देना चाहिए की बात लोगों द्वारा की जा रही है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422